शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 12 | अंक : 287 | गुवाहाटी | रविवार, 24 मई, 2026 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

यूपी में वक्फ संपत्तियों पर सख्ती, 31 हजार से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन रद्द पेज 2
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर फ्लाईओवर का नामकरण करने... पेज 3
रेल मंत्री ने जयपुर में 420 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र पेज 5
आईपीएल 2026 : ऑरेंज कैप रेस में क्लासेन तीसरे स्थान पर, ईशान किशन टॉप-5... पेज 7

असम के विकास रोडमैप को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम

गुवाहाटी (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के भविष्य के विकास और आर्थिक प्रगति को लेकर विस्तृत चर्चा की। यह बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री के आधिकारिक आवास पर आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछले पांच वर्षों में असम को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से राज्य में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति मिली है। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद सोशल मीडिया पर साझा संदेश में कहा कि उन्होंने असम को मिले निरंतर सहयोग के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा आने वाले वर्षों में राज्य के विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा तथा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ केके द्विवेदी भी उपस्थित रहे। सूत्रों के अनुसार, चर्चा के दौरान असम की आर्थिक वृद्धि, आधारभूत संरचना विस्तार और निवेश की संभावनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकार वर्तमान में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना परियोजनाओं, औद्योगिक निवेश तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। बैठक में वित्तीय सहायता, विकास परियोजनाओं तथा भविष्य के निवेश अवसरों से संबंधित विषय भी प्रमुखता से उठाए गए। दोनों नेताओं ने राज्य में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया। पिछले कुछ -शेष पृष्ठ दो पर

चीन की कोयला खदान में धमाका, 90 की गई जान

बीजिंग (हि.स.)। चीन के शांक्सी प्रांत स्थित लियुशेन्यु कोयला खदान में शुक्रवार रात हुए भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है, जबकि कई मजदूर अभी भी लापता हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग ने राहत एवं बचाव कार्य में पूरी ताकत झोंकने और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शनिवार को बताया कि विस्फोट शुक्रवार को शाम 7.29 बजे शांक्सी प्रांत के किनयुआन काउंटी में हुआ। यह इलाका बीजिंग से करीब 520 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। हादसे से पहले खदान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अलर्ट जारी किया गया था। इसके कुछ ही समय बाद भीषण विस्फोट हुआ। विस्फोट के वक्त खदान में 247 मजदूर काम कर रहे थे। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग अब भी अंदर फंसे हुए हैं। राहत एवं बचाव अभियान जारी है। काउंटी के आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो के अनुसार, कोयला खदान दुर्घटना में 82 लोगों की मौत हो गई है, जबकि नौ अन्य अभी भी लापता हैं। विस्फोट के वक्त 200 से ज्यादा लोग खदान के अंदर मौजूद थे। कुल 123 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है, जबकि 119 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ब्यूरो के मुताबिक राहत एवं बचाव दल और चिकित्सा कर्मियों सहित 755 लोगों को घटनास्थल पर भेजा गया है। आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने कहा कि उसने बचाव कार्यों में सहायता के लिए छह राष्ट्रीय खदान आपातकालीन बचाव दल भेजे हैं, जिनमें कुल 345 लोग शामिल हैं। किनयुआन काउंटी से लगभग 130 किमी दूर स्थित लिचेंग काउंटी के एक डॉक्टर ने बताया कि उन्हें -शेष पृष्ठ दो पर

बकरीद पर गाय की कुर्बानी के खिलाफ मुसलमानों की अपील का मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार (23 मई, 2026) को राज्य की विभिन्न ईदगाह और कब्रिस्तान समितियों द्वारा जारी बयानों का स्वागत किया, जिसमें मुसलमानों से बकरीद या ईद-उल-जुहा के दौरान गायों की कुर्बानी न देने का आग्रह किया गया है। पिछले कुछ दिनों में, कम से कम चार जिलों - बंगाईगांव, कछार, धुबड़ी और होजाई में ईदगाह समितियों ने समुदाय के सदस्यों से बकरीद के दौरान गायों का वध करने से परहेज करके गैर-मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की है। ईदगाह के प्रतिनिधियों ने मुसलमानों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए गायों के -शेष पृष्ठ दो पर

संरक्षण प्रयासों से असम में लुप्तप्राय ढोलों के पुनरुद्धार में मदद मिली : डॉ. शर्मा

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए संरक्षण उपायों के कारण काजीरंगा-कार्बी आंग्लांग क्षेत्र में लुप्तप्राय एशियाई जंगली कुत्ते, या ढोल की आबादी में पुनरुत्थान हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटनाक्रम को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि यह प्रजाति, जो कभी इस क्षेत्र के जंगलों में आम तौर पर पाई जाती थी, समय के साथ धीरे-धीरे गायब हो गई थी, लेकिन हाल के वर्षों में इसके लौटने के संकेत उभरने लगे हैं। ढोल को एक शांत लेकिन अत्यंत प्रभावी शिकारी बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वन क्षेत्र की रक्षा और विस्तार करने, पर्यावास संपर्क में सुधार करने और अतिक्रमण की गई वन भूमि को साफ करने के लिए सरकार के प्रयास क्षेत्र में -शेष पृष्ठ दो पर

doorgraph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है, जैसे पौधों में फूल और फल अपने समय पर आते हैं।

-वृंद

तेलंगाना में लू से 16 लोगों की मौत

हैदराबाद (हि.स.)। तेलंगाना में भीषण गर्मी के बीच लू से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें राज्य के सात अलग-अलग जिलों में हुई हैं। राज्य के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को यह जानकारी दी। सरकार ने मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। शनिवार को तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हीटवेव की वजह से पैदा हुए हालात पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि जयशंकर भूपालपल्ली जिले में चार, वारंगल शहरी, करीमनगर और निजामाबाद में -शेष पृष्ठ दो पर

प्रधानमंत्री ने 51 हजार युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा-

विकसित भारत में युवाओं की होगी बड़ी भूमिका

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 19वें रोजगार मेले में 51 हजार से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि देश का युवा विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाला है और आने वाले वर्षों में नई अर्थव्यवस्था तथा टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन देशभर के हजारों युवाओं और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नियुक्ति पाने वाले युवा रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं तथा वे देश की विकास यात्रा के जिम्मेदार भागीदार बनेंगे। मोदी ने कहा कि हाल ही में उनकी पांच देशों की यात्रा के दौरान दुनिया की बड़ी कंपनियों के प्रमुखों से विस्तृत चर्चा हुई और हर जगह भारत के युवाओं तथा देश की तकनीकी प्रगति को लेकर उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है और भारत विभिन्न देशों के साथ साझेदारी बढ़ाकर युवाओं के लिए नए अवसर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वीडन, नॉर्वे और इटली -शेष पृष्ठ दो पर

माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली असम की पहली महिला बनीं रूपामणि गौढ़

गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार (23 मई, 2026) को घोषणा की कि रूपामणि गौढ़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली असम की पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने यह उपलब्धि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की एक महिला अभियान दल के हिस्से के रूप में हासिल की। लखीमपुर जिले के लीलाबाड़ी की निवासी गौढ़ ने गुरुवार (21 मई, 2026) को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के शिखर पर विजय प्राप्त की। शर्मा ने कहा कि राज्य को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि असम की बेटी ने दुनिया के शिखर -शेष पृष्ठ दो पर

ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका, तुलसी गबार्ड ने छोड़ा इंटेलिजेंस चीफ का पद

नई दिल्ली (हि.स.)। अमेरिका में खुफिया एजेंसियों की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में तुलसी गबार्ड को अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों पर निगरानी रखने वाली राष्ट्रीय खुफिया संस्था का निदेशक नियुक्त किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुलसी गबार्ड का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है तथा उनके सहायक उपनिदेशक आरोन लुकास को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तुलसी आगामी 30 जून को पदमुक्त होंगी। राष्ट्रपति ट्रंप को भेजे गए अपने त्यागपत्र में तुलसी ने अपने पति अब्राहम की बीमारी का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे पति एक दुर्लभ किस्म के हड्डियों के कैंसर से पीड़ित हैं। वह पति की -शेष पृष्ठ दो पर

मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से की मुलाकात

वैश्विक हित में मिलकर काम करेंगे भारत और अमेरिका : प्रधानमंत्री

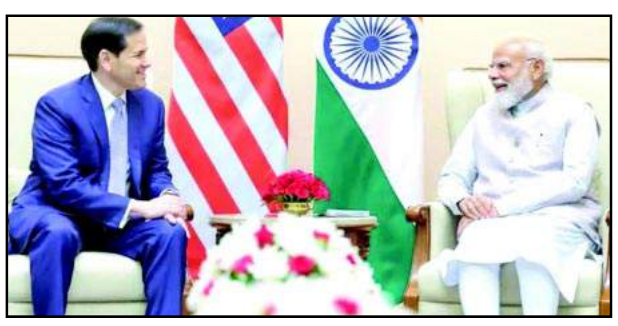

नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मार्को रूबियो के साथ फोटो शेयर की हैं। -शेष पृष्ठ दो पर

एससी में चुनौती के बीच *त्रि-भाषा सूत्र* के समर्थन में उतरे शिक्षाविद

नई दिल्ली (हि.स.)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 9-10 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के *त्रि-भाषा सूत्र* को उच्चतम न्यायालय में दी गई कानूनी चुनौती के बीच शिक्षा जगत और भाषाविदों ने इसमें भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए अनिवार्य कदम बताया है। शिक्षा जगत के बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों के मानसिक विकास और देश की संस्कृति को बचाने के लिए कक्षा 9-10 में -शेष पृष्ठ दो पर

भारत-चीन सीमा से सटे पोलिंग बूथों का ईसी ने किया निरीक्षण

उत्तरकाशी (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर शनिवार को उत्तरकाशी पंहुचे। उन्होंने भारत-चीन सीमा से सटे उत्तरकाशी जिले के सीमांत पोलिंग बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत पोलिंग बूथ का -शेष पृष्ठ दो पर

तेल संकट से बढ़ी टेंशन, वर्ल्ड बैंक के पास मदद मांगने पहुंचे 27 देश

नई दिल्ली। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के 27 देशों ने इमरजेंसी फंड की मांग की है। इन देशों ने ऐसे सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिनके जरिए जरूरत पड़ने पर वे जल्दी से विश्व बैंक से फंड ले सकें। रॉयटर्स को मिले एक आंतरिक दस्तावेज में बताया गया है कि इन देशों के नाम और मांगी गई रकम की जानकारी नहीं दी गई है। वर्ल्ड बैंक ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक, 28 फरवरी से मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ने के बाद तीन देशों ने नए क्राइसिस सपोर्ट सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जबकि बाकी देश अभी इसकी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से कई देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता की वजह से सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा खाद की सप्लाई भी रुक रही है, जिससे खेती पर असर पड़ रहा है। केन्या और इराक ने -शेष पृष्ठ दो पर

अफ्रीकी देश में सत्ता विस्फोट

सेनेगल के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को किया आऊट, भंग कर दी पूरी सरकार

डैकर। सेनेगल में बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रपति बसिरु डियोमाये फेय ने प्रधानमंत्री ओस्मान सोनको को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही पूरी सरकार भी भंग कर दी गई। सरकारी मीडिया के जरिए यह घोषणा की गई। सरकार के सभी मंत्रियों को भी हटा दिया गया है। फिलहाल पुरानी सरकार को सिर्फ रोजमर्रा का काम संभालने को कहा गया है। फेय और सोनको पहले बहुत करीबी सहयोगी माने जाते थे। 2024 के चुनाव में सोनको चुनाव नहीं लड़ पाए थे, इसलिए उन्होंने फेय का समर्थन किया था। दोनों ने मिलकर पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों नेताओं के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे। आर्थिक नीतियों और सरकारी फैसलों को लेकर दोनों के बीच -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

यूपी में वक्फ संपत्तियों पर सख्ती, 31 हजार से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन रद्द

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में साफ-सफाई का बड़ा अभियान चल रहा है और इस वजह से लगातार रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा रहे हैं। अब तक *उम्मीद* पोर्टल पर 31 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि जांच के दौरान इन वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में कई तरह की खामियां मिली हैं। उम्मीद पोर्टल पर दर्ज 1,18,302 संपत्तियों में से 31,328 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इनमें कई पुरानी कब्रिस्तानों और दरगाहों की संपत्तियां भी शामिल हो सकती हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से पिछले साल 5 जून को शुरू किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया चल रही है। शुरुआती दौर में 6 महीने का समय दिया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अपील पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने रजिस्ट्रेशन कराने की मियाद और 6 महीने के लिए बढ़ा दी थी। यह अतिरिक्त समय अगले महीने 5 जून को खत्म हो रहा है। सिर्फ 53 हजार से अधिक संपत्तियों को मंजूरी मिल सकी है। अभी तक पोर्टल पर दर्ज कुल 1,18,302 संपत्तियों में से महज 53,711 को स्वीकृति मिल सकी है, जबकि 20,546 संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच अंतिम चरण में है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 31,192 संपत्तियों के वक्फ दावे को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई संपत्तियों में कई कब्रिस्तान-दरगाह पर संकट मंडरा रहा है। रद्द किए गए मामलों में कई तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे कि खसरा नंबर में वक्फ बोर्ड और राजस्व अभिलेखों में मेल नहीं खाना। रकबा (क्षेत्रफल) में भारी अंतर का होना। एक ही संपत्ति का दो अलग-अलग वक्फ बोर्ड में दर्ज होना। इसके अलावा दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटियां और कई पुरानी गलतियों का होना। प्रदेश के कई जिलों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। इसमें सबसे अधिक जौनपुर में रद्द किए गए हैं। इसके बाद बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बस्ती, और सीतापुर का नंबर आता है। जौनपुर में जहां 1,938 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है तो वहीं बाराबंकी में 1521, मुजफ्फरनगर में 1510, अलीगढ़ में 1061, बस्ती में 1000, उन्नाव में 908, सीतापुर में 906, हरदोईमें 891, आजमगढ़ में 886 और लखनऊ में 875 संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। जौनपुर, बाराबंकी और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में यह समस्या सबसे ज्यादा उभरी है। नियम के अनुसार समय सीमा बढ़ाने की सीमित व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे वाले प्रावधानों के बावजूद ट्रिब्यूनल पहले ही अधिकतम समय दे चुका है। अब मुतवल्लियों को व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, जो कानूनी रूप से जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। हालांकि वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का यह भी कहना है कि मुतवल्लियों के पास अभी 5 जून तक का समय है। वे सही दस्तावेजों के साथ दोबारा संपत्ति अपलोड कर सकते हैं।

एसीएस अधिकारी लाचित दास की मुश्किलें बढ़ीं रिश्तेदार के फ्लैट से करोड़ों की नकदी बरामद

गुवाहाटी (हिंस)। घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए असम सिविल सेवा (एसीएस) अधिकारी लाचित कुमार दास की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी में उनकी शाली के फ्लैट से 1 करोड़ 17 लाख 30 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, कल तलाशी अभियान के दौरान अधिकारी के घर से 50 लाख रुपए से अधिक नकद तथा 500 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण बरामद हुए थे। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह संपत्ति आय से अधिक हो सकती है। बरामद नकदी और आभूषणों के स्रोत को लेकर अब विस्तृत वित्तीय जांच शुरू कर दी गई है। लाचित कुमार दास भूमि अभिलेख निदेशालय में अतिरिक्त भूमि अभिलेख अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्हें गुरुवार को 45 हजार रुपए की घूस लेते समय सतर्कता टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की थी। गिरफ्तारी के बाद सतर्कता विभाग ने उनसे जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान नकदी, आभूषणों के अलावा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं। जांचकर्ता अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि बरामद संपत्ति अवैध कमाई से अर्जित की गई थी या इसके पीछे किसी बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क का संबंध है।

चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

35 दिन में श्रद्धालुओं की संख्या बीस लाख के पार

देहरादून (हि.स.)। उत्तराखंड की विश्वप्रसिद्ध केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारधाम यात्रा इस वर्ष आस्था और उत्साह के नए रिकॉर्ड बना रही है। यात्रा में अब तक श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार को एक दिन में रिकॉर्ड 96 हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम प्रतिकूल होने पर हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। शनिवार को रिकॉर्ड 96 हजार 116 तीर्थयात्रियों ने चारधाम के दर्शन किए। कुल दर्शनार्थियों का आंकड़ा 20 लाख 76 हजार को पार कर चुका है जबकि केदारनाथ में 08 लाख 11 हजार से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र की यात्रा होने से आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यात्रा का विगत 19 अप्रैल को श्रीगणेश हुआ था और आज शनिवार 23 मई तक यानी 35 दिनों में 20 लाख 76 हजार 553 श्रद्धालु चारधाम दर्शन कर चुके हैं। इनमें केदारनाथ में 8,11,923, बद्रीनाथ में 5,56,437, गंगोत्री में 3,52,162 और यमुनोत्री धाम में 3,56,031 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। आज शनिवार को एक दिन में ही चारों धामों में 96 हजार 116 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ में सर्वाधिक 32,219 तीर्थयात्री पहुंचे। जबकि केदारनाथ में 29,787, यमुनोत्री में 16,213 और गंगोत्री धाम में 17,897 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

मप्र के सीधी में बिजली लाइन में स्पार्किंग से कच्चे मकान में लगी आग, जिंदा जले तीन मासूम

सीधी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ग्राम कसिहवा में शनिवार को एक कच्चे मकान में लगी भीषण आग में तीन मासूम बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरे घर को चपेट में ले लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत ही दुखद है। मृत बच्चों के परिजन को 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जानकारी के अनुसार सीधी जिले के गोपद बनास तहसील अंतर्गत ग्राम कसिहवा में शनिवार दोपहर करीब एक बजे रामरतन साकेत के घर के पास बिजली के पोल से शार्ट-सर्किट होने से आग लग गई, जिसमें रामरतन की दो बेटियां कुमारी घुम्मु उर्फ संध्या साकेत (लगभग 6 वर्ष) कुमारी रिद्धि (लगभग 1.6 वर्ष) एवं एक बेटा नागेन्द्र (लगभग 3 वर्ष) की दर्दनाक मृत्यु हो गई। प्रत्यक्षदर्शी गांव के पुष्पराज मिश्रा ने बताया कि घर के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन में स्पार्किंग हुई। चिंगारी पास में रखे बांस और सूखे सामान पर गिरी, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। देखते ही देखते पूरा कच्चा मकान आग की लपटों में घिर गया। घटना के समय घर बाहर से बंद था और अंदर तीनों बच्चे मौजूद थे। बच्चों की मां घर से जाते समय दरवाजा बाहर से बंद कर गई थी, जिससे बच्चे अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन तब तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। बच्चों के पिता रामरतन साकेत ने बताया कि उन्हें उनके सुपरवाइजर का फोन आया था, जिसने घर में आग लगने की जानकारी दी। उस समय उनकी पत्नी राशन लेने दुकान गई थी, जबकि तीनों बच्चे घर में अकेले थे। रामरतन साकेत ने बताया कि उनके चार बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा हैं। बड़ी बेटी स्कूल की छुट्टियों के कारण नानी के घर गई हुई थी। दूसरे नंबर की बेटी रिधि कक्षा एक में पढ़ती थी। हादसे में रिधि समेत तीन मासूमों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। केस दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। वहीं, जानकारी मिलते ही सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट हुई ब्लॉक

नई दिल्ली। इंटरनेट पर सनसनी बनी कॉकरोच जनता पार्टी की बहुचर्चित वेबसाइट को शनिवार को इंटरनेट से हटा दिया गया है। इसके संस्थापक अभिजीत दिपके ने पुष्टि की है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए इसे सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया है। अभिजीत दिपके का यह अजीब लेकिन वायरल डिजिटल अभियान युवा सोशल मीडिया यूजर्स के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है, ने एक्स पर सरकार पर भड़ास निकाली। उन्होंने दावा किया कि लगभग 10 लाख लोगों ने उनकी वेबसाइट पर सदस्य के रूप में साइन अप किया था। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेनियल्स और जेन-जी युवाओं के लिए मौजूदा व्यवस्था पर मीम और कटाक्ष के जरिए निशाना साधने का एक बड़ा मंच बन गया था। यह पूरा विवाद कथित नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच सामने आया है, जिसने देशभर के लाखों मेडिकल छात्रों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। दिपके ने दावा किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के छह लाख सदस्यों ने परीक्षा विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली पिटीशन पर हस्ताक्षर भी किए थे। एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए दिपके ने पोस्ट किया कि सरकार ने हमारी आइकॉनिक वेबसाइट को हटा दिया है। 10 लाख कॉकरोचों ने हमारी वेबसाइट पर सदस्य के रूप में साइन अप किया था। 6 लाख कॉकरोचों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार कॉकरोचों से इतना क्यों डरती है? लेकिन यह तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखें खोल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का यह ट्रेंड पहली बार तब ऑनलाइन वायरल हुआ था, जब एक वकील को वरिष्ठ का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा कथित तौर पर की गई एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उस घटना के बाद से, यह डिजिटल मूवमेंट हास्य, व्यंग्य और सत्ता-विरोधी टिप्पणियों से लैस एक व्यापक *इंटरनेट विद्रोह* में बदल गया है, जिसे खासकर युवा सोशल मीडिया यूजर्स का भारी समर्थन मिल रहा है।

पृष्ठ एक का शेष

असम के विकास...

वर्षों में असम में सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े निवेश हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में व्यापार सुगमता बढ़ाने और निजी निवेश आकर्षित करने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चर्चा आने वाले वर्षों में असम के विकास की नई दिशा तय करने के उद्देश्य से की गई। राज्य सरकार असम को पूर्वोत्तर भारत के एक उभरते आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसमें आधारभूत संरचना, पर्यटन, सेमीकंडक्टर निर्माण, हरित ऊर्जा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

चीन की कोयला खदान...

सुबह 4 बजे आदेश मिला और वे तुरंत उपकरणों और दवाओं के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल, अन्य चिकित्सा एवं बचाव दलों के साथ मिलकर वे घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि खदान दुर्घटना में शामिल कंपनी के ज़िम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार हिरासत में ले लिया गया है। चीन की स्टेट काउंसिल द्वारा भेजी गई एक जांच टीम ने इस दुर्घटना की पूरी तरह और सख्ती से जांच करने का वादा किया है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने हादसे के बाद बचाव टीमों को लापता लोगों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी क्षेत्रों और सरकारी विभागों को इस हादसे से सबक लेना चाहिए, कार्यस्थल सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए और बड़े हादसों को रोकने के लिए जोखिमों की पूरी जांच करनी चाहिए। चीनी प्रधानमंत्री कियांग ने कहा कि लापता मजदूरों को खोजने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने हादसे की विस्तृत जांच करवा कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा चीन में पिछले एक दशक का सबसे बड़ा कोयला खदान हादसा माना जा रहा है। चीन ने बीते कुछ साल में खदान सुरक्षा नियमों को सख्त किया है, इसके बावजूद वहां खदान हादसे लगातार हो रहे हैं। कोयला उत्पादन बढ़ाने के दबाव और कई जगह सुरक्षा मानकों में लापरवाही को इसकी बड़ी वजह माना जाता है। उल्लेखनीय है कि चीन में अब भी ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। देश की आधे से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें कोयले से पूरी होती हैं। शांक्सी प्रांत चीन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा यहीं की खदानों से पूरा होता है। हालांकि, लगातार उत्पादन के दबाव की वजह से यहां सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। पिछले महीने भी शांक्सी के लुलियांग क्षेत्र में एक खदान हादसा हुआ था, जिसमें चार मजदूरों की मौत हो गई थी।

बकरीद पर गाय की...

अलावा अन्य जानवरों की कुर्बानी देने पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ समाजों में गायों का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है और उन्होंने सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन समितियों द्वारा जारी किए गए बयानों की समाचार पत्रों की कटिंग और प्रतियां साझा करते हुए कहा कि यह पहल राज्य में बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं के प्रति सम्मान को दर्शाती है। शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं होजाई, धुबड़ी, बंगाईगांव, उदारबंद (कछार जिला) और अन्य स्थानों की ईदगाह समितियों की पहलों का स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया है। इस तरह के स्वैच्छिक कार्यों से असम में सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि अन्य ईदगाह समितियां भी इसी तरह की अपील जारी करेंगी।

संरक्षण प्रयासों से ...

पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में मदद कर रहे हैं। शर्मा के अनुसार, वन्यजीव निगरानी प्रयासों के माध्यम से इस पुनरुद्धार को प्रलेखित किया गया है। जबकि 2022 में कैमरा ट्रैप इमेज में केवल एक ढोल ही कैद हुआ था, अधिकारियों ने अब प्रत्यक्ष अवलोकन की रिपोर्ट दी है और 2026 में पूरे झुंड की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसे *पुनरुद्धार की एक सशक्त कहानी* बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक शीर्ष शिकारी की वापसी व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण को दर्शाती है और सतत संरक्षण पहलों की सफलता को उजागर करती है। ढोल, जिन्हें एशियाई जंगली कुत्ते के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर इनकी घटती आबादी के कारण, इस प्रजाति को वर्तमान में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन) द्वारा *लुप्तप्राय* श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

तेलंगाना में लू से ...

तीन-तीन, जबकि जोगुलांबा गडवाल, रंगारेड्डी और सूर्यापेट जिलों में एक-एक व्यक्ति की जान गई है। राजस्व मंत्री रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मंडलों और गांवों में तापमान सबसे अधिक दर्ज किया जा रहा है, वहां के निवासियों को पहले से चेतावनी जारी की जाए। बस स्टैंड, बाजारों और मजदूरों के जमावड़े वाले प्रमुख स्थानों पर ठंडा पेयजल, छाछ और ओआरएस पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव जीवन की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे तीन दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने लोगों से अपील की थी कि वे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। विशेष रूप से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को इस दौरान घर के अंदर ही रहने की सलाह दी थी, जब तक कि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य न हो। मौसम विभाग के अनुसार, तेलंगाना में भीषण गर्मी और लू की स्थिति 26 मई तक बनी रहने की संभावना है। विशेष रूप से करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबनगर, हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

विकसित भारत में ...

जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ने से भारत भविष्य की क्लीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मजबूत होगा। यूएई और नॉर्वे के साथ साझेदारी से भारत का शिपबिल्डिंग इकोसिस्टम भी मजबूत होगा, जिससे इंजीनियरों, टेक्निशियनों और स्किल्ड वर्कर्स की मांग बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि देश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन विकसित की जा रही है। आने वाले वर्षों में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स वैश्विक स्तर पर पहचान बनाएंगी और इनमें युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। मोदी ने कहा कि गांवों में बढ़ती कनेक्टिविटी से किसानों, छोटे व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए नए अवसर खुले हैं। उन्होंने नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि आज बड़ी संख्या में महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप सामने आ रहे हैं और मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से सार्वजनिक सेवा को राष्ट्रसेवा और जनसेवा का माध्यम मानकर कार्य करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि देशभर में आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक करीब 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को रेल, गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग समेत विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में नियुक्ति दी गई।

वैश्विक हित में मिलकर ...

पीएम मोदी ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का स्वागत करके मुझे खुशी हुई। पीएम मोदी ने मार्को रूबियो से हुई मुलाकात के बारे में बताते हुए एक्स पर लिखा कि हमने भारत-यूएस व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी और विदेश मंत्री रूबियो के बीच हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और अमेरिकी उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर मौजूद थे। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस बैठक को सार्थक बताते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में मार्को रूबियो के साथ शामिल होना बहुत अच्छा लगा। हमने सुरक्षा, व्यापार और अहम टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अमेरिका-भारत सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की। अमेरिकी राजदूत ने भारत को अहम साझीदार बताते हुए आगे लिखा कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे दोनों देशों को मजबूत बनाते हैं और एक स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। भारत, अमेरिका का एक अहम साझीदार है। अमेरिकी राजदूत के अनुसार, आगामी मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना होगा। इनमें रक्षा साझेदारी, उन्नत टेक्नोलॉजी, व्यापारिक संबंध और क्वाड्रीलिटरल सिक्योरिटी डायलॉग (क्वाड) के तहत आपसी सहयोग शामिल हैं।

एससी में चुनौती के ...

भारतीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ाना बेहद जरूरी है। भाषाविदों के अनुसार सीबीएसई का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिल्कुल अनुकूल है, जो बहुभाषिकता और मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर देती है। अंतर्राष्ट्रीय शोध भी प्रमाणित करते हैं कि बच्चे अपनी परिचित भाषा में अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। उनका मानना है कि देश के एक सीमित अभिजात्य वर्ग या विदेशी भाषा समर्थक समूहों की आकांक्षाओं के चलते करोड़ों सामान्य विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषाओं के अध्ययन से वंचित नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने शनिवार को अपने जारी बयान में कहा कि भारत की भाषाएं केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और ज्ञान परंपरा की आधारशिला हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) भारतीय भाषाओं को शिक्षा तथा अनुसंधान के केंद्र में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है और सीबीएसई का त्रि-भाषा सूत्र (मॉडल) इसी दूरदर्शी सोच का व्यावहारिक स्वरूप है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा तक किसी भारतीय भाषा का अध्ययन करते आए हैं, उन्हें माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 और 10) पर भी इस भाषाई निरंतरता का अवसर मिलना चाहिए। मातृभाषा तथा भारतीय भाषाओं में शिक्षा से विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास, आत्मविश्वास और सृजनात्मक क्षमता को मजबूती मिलती है। कुलपति ने कहा कि भारतीय भाषाओं के संवर्धन का अर्थ किसी विदेशी भाषा का विरोध करना कतई नहीं है। भारत हमेशा से वैश्विक ज्ञान के प्रति उदार रहा है लेकिन अपनी भाषाई जड़ों को कमजोर करके कोई भी राष्ट्र लंबे समय तक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी नहीं रह सकता। उन्होंने भारतीय भाषाओं के अध्ययन से होने वाले 5 प्रमुख लाभों का जिक्र किया। इनमें बौद्धिक व रचनात्मक विकास, शैक्षिक समानता, सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होना और विद्यार्थियों के हित में निरंतरता शामिल है। शिक्षा और संस्कृति से जुड़े विद्वानों ने अब इस मुद्दे पर देशव्यापी सकारात्मक जन-जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए त्रि-भाषा सूत्र लागू करने वाला है। इसके तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। इस नियम के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें इस व्यवस्था का विरोध किया गया है।

भारत-चीन सीमा से ...

निरीक्षण किया और बूथ लेवल अधिकारी मिंटो देवी से विस्तृत संवाद किया। उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धिकरण, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण और डिजिटल मॉनिटरिंग की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बीएलओ ऐप के माध्यम से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और विदेशी मतदाताओं की पहचान कर मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ मिंटो देवी के कार्यों की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि दुर्गम सीमांत क्षेत्र में समर्पण और दक्षता के साथ किया जा रहा उनका कार्य पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में जुटे सभी बीएलओ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के वास्तविक प्रहरी हैं और चुनाव आयोग उनके समर्पण को सलाम करता है। दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने गंगोत्री धाम पहुंचकर परिवार सहित मां गंगा के दर्शन और विशेष पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गंगोत्री स्थित विशेष पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया, जहां अधिकांश मतदाता साधु-संत और संन्यासी समुदाय से जुड़े हैं। साधु-संतों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्गम हिमालयी क्षेत्र में स्थित ऐसा मतदान केंद्र, जहां शत-प्रतिशत मतदाता तप और साधना में लीन संत समाज से जुड़े हों, भारतीय लोकतंत्र की विविधता और व्यापकता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के लिए संत समाज की सराहना की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा भी की। इस दौरान सीमांत क्षेत्रों में मतदाता सूची अद्यतन, बूथ मैपिंग और चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

माउंट एवरेस्ट पर ...

पर अपनी जगह बना ली है। आईटीबीपी की महिला अभियान टीम के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली असम की पहली महिला बनने पर रूपामणि गौढ़ को हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे कहा कि उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि असम के लिए अपार गर्व का क्षण है और हमारे युवाओं के लिए बड़े सपने देखने और नई ऊंचाइयों को हासिल करने की प्रेरणा है। किसान परिवार में जन्मीं गौढ़ लीलाबाड़ी में साधारण परिवेश में पली-बढ़ीं। उनके पिता, जॉयसिंह गौढ़, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जबकि उनकी माता, कमलवती, आंगनवाड़ी सहायक के रूप में काम करती हैं। कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद, वह 2020 में आईटीबीपी में शामिल हुईं और रोमांच और पर्वतारोहण के प्रति अपने बचपन के जुनून को आगे बढ़ाती रहीं, उनके परिवार ने बताया।

तेल संकट से बढ़ी ...

पुष्टि की है कि उन्होंने विश्व बैंक से जल्दी आर्थिक मदद मांगी है। केन्या में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि इराक को तेल से होने वाली कमाई में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये 27 देश उन 101 देशों में शामिल हैं जिन्हें पहले से तैयार क्राइसिस फंड सिस्टम का फायदा मिल सकता है। इनमें से 54 देश रैपिड रिस्पॉन्स योजना का हिस्सा हैं। इस योजना के तहत कोई भी देश अपने मंजूर लेकिन अभी तक इस्तेमाल न किए गए फंड का 10 प्रतिशत तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने पिछले महीने कहा था कि जरूरत पड़ने पर बैंक 20 से 25 अरब डॉलर तक की तुरंत आर्थिक मदद उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने कहा कि पुराने प्रोजेक्ट्स के बचे हुए फंड और दूसरी योजनाओं को मिलाकर अगले छह महीनों में यह मदद 60 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। आगे चलकर यह रकम 100 अरब डॉलर तक भी जा सकती है। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टलीना जार्जिवा ने कहा था कि करीब 12 देश आईएमएफ से भी मदद मांग सकते हैं। हालांकि अभी बहुत कम देशों ने आधिकारिक रूप से आवेदन किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई देश आईएमएफ की बजाय वर्ल्ड बैंक से मदद लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ आमतौर पर खर्च में कटौती जैसी सख्त शर्तें लगाता है। इससे पहले से परेशान देशों में आर्थिक और सामाजिक संकट और बढ़ सकता है।

सेनेगल के राष्ट्रपति ...

तनाव खुलकर सामने आने लगा था। सेनेगल इस समय बड़े आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। इंटरनेशनल मोनिटरी फंड ने देश का 1.8 अरब डॉलर का लोन प्रोग्राम रोक दिया है। वजह देश के कर्ज से जुड़े आंकड़ों में गड़बड़ी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश पर कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। सरकार पर ईंधन सब्सिडी का भी भारी बोझ है। वित्त मंत्री ने ईंधन कीमतें बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन सोनको इसके खिलाफ थे। सोनको युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। उनकी बर्खास्तगी के बाद अब सेनेगल में राजनीतिक तनाव और विरोध बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

ट्रंप प्रशासन को बड़ा ...

देखभाल के लिए समय चाहती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर तुलसी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमें उनकी कमी खलेगी। तुलसी ने अपने त्यागपत्र में ईरान युद्ध या अन्य मुद्दों पर ट्रंप प्रशासन की नीतियों से किसी असहमति का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह आम चर्चा थी कि तुलसी गबार्ड ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसके खिलाफ छेड़े गए युद्ध के खिलाफ थीं। पिछले कुछ महीनों के दौरान ट्रंप प्रशासन के कई मंत्रियों और अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर फ्लाईओवर का नामकरण करने पर मुख्यमंत्री का भाजपा ने जताया आभार

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश भाजपा ने गुवाहाटी के लालगणेश स्थित नवनिर्मित फ्लाईओवर का नाम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा का आभार व्यक्त किया है। पार्टी ने कहा कि यह निर्णय समय की मांग थी और डॉ. मुखर्जी के असम तथा असमिया समाज के प्रति योगदान को सम्मान देने वाला कदम है। प्रदेश भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट दिलीप कुमार शर्मा ने आज जारी एक बयान में कहा कि स्वतंत्रता के बाद असम को ग्रुपिंग योजना के माध्यम से पाकिस्तान में शामिल करने की साजिश के खिलाफ असम के प्रथम मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै के नेतृत्व और दृढ़ता को डॉ. मुखर्जी ने खुला समर्थन दिया था। उन्होंने दावा किया कि उस समय जब जवाहरलाल नेहरू ग्रुपिंग व्यवस्था के पक्ष में थे, तब महात्मा गांधी की कड़ी भूमिका और डॉ. मुखर्जी के प्रत्यक्ष सहयोग ने गोपीनाथ बरदलै को इसके खिलाफ संघर्ष करने का

साहस और प्रेरणा प्रदान की। बयान में कहा गया कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940-41 के दौर में असम के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रखर राष्ट्रवादी तथा असम हितैषी नेता के रूप में स्वयं को स्थापित किया। दिलीप कुमार शर्मा ने यह भी कहा कि डॉ. मुखर्जी ने असमिया भाषा को माध्यम के रूप में स्थापित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने कहा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए डॉ. मुखर्जी ने मातृभाषा आधारित शिक्षा को महत्व दिया और असमिया भाषा को कक्षा 10 तक माध्यम के रूप में मान्यता दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जेबी कालेज को मान्यता दिलाने में भी डॉ. मुखर्जी की भूमिका रही। बयान में आगे कहा गया कि डॉ. मुखर्जी ने असम में विश्वविद्यालय स्थापना आंदोलन को प्रोत्साहित किया। साथ ही उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में असमिया भाषा को स्थापित करने का श्रेय भी दिया गया। भाजपा ने कहा कि असम हितैषी और महान व्यक्तित्व के धनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान में किसी संस्थान, सड़क या फ्लाईओवर का नामकरण करना समय की आवश्यकता थी। पार्टी ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को पुनः धन्यवाद ज्ञापित किया।

गुवाहाटी में 26 दुर्लभ टोकाय गेको बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी (हिंस)। असम पुलिस ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुवाहाटी में बीती देर रात अभियान चलाकर 26 दुर्लभ एवं संकटग्रस्त टोकाय गेको (छिपकली) बरामद किए तथा इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा आज दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विशेष सूचना के आधार पर बशिष्ठ इलाके के समीप यह अभियान चलाया गया। आरोपी इन दुर्लभ जीवों को अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) की ओर ले जा रहे थे, जहां से इन्हें राज्य के बाहर तस्करी कर भेजने की योजना थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तस्कर इन टोकाय गेको को कार्बी आंग्लांग से मोटरसाइकिल के जरिए लेकर आए थे। कार्बी आंग्लांग को पूर्वोत्तर में वन्यजीव तस्करी का एक प्रमुख ट्रांजिट रूट माना जाता है। असम पुलिस ने इस बरामदगी को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है।

बकरीद से पहले सीएम को कथित धमकी देने के आरोप में पूर्व विधायक अली अकबर मियां गिरफ्तार

धुबड़ी (हिंस)। बकरीद से पहले गो-कुर्बानी को लेकर विवादित टिप्पणी करने तथा मुख्यमंत्री को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार बिलासीपाड़ा के पूर्व विधायक अली अकबर मियां से धुबड़ी पुलिस ने पूरी रात पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शनिवार तड़के उनकी तबीयत बिगड़ गई। पूर्व विधायक की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल धुबड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। उपचार के बाद पुलिस उन्हें पुनः धुबड़ी सदर थाना लेकर आई, जहां उनसे पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार, अपराध अनुसंधान शाखा के उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूर्व विधायक से पूछताछ की जा रही है। वहीं, आज अली अकबर मियां को अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।

कोकराझाड़ : फकीराग्राम डेली मार्केट में भीषण आग, पान की दुकान जलकर राख

कोकराझाड़ (विभास)। जिले के फकीराग्राम डेली मार्केट में बीती रात आग लगने से एक पान की दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना में दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। मिली जानकारी के अनुसार, आग रात करीब 11-30 बजे लगी। स्थानीय लोगों ने जब पान की दुकान से लपटें उठती देखीं, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। आग की सूचना मिलते ही फकीराग्राम पुलिस और दमकल विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। दमकलकर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिससे आग को आसपास की अन्य दुकानों में फैलने से रोक लिया गया। दुकानदार आनारुल इस्लाम ने बताया कि इस अगजनी की घटना में उनकी दुकान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बकरीद पर बाक्सा के माधोपुर में नहीं होगी गो-धन की कुर्बानी

बाक्सा (हिंस)। असम के बाक्सा जिले के माधोपुर जामा मस्जिद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सौ से अधिक मुस्लिम परिवारों ने इस बार बकरीद के अवसर पर गो-धन की कुर्बानी नहीं देने का निर्णय लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि वे किसी भी तरह से हिंदू समाज की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, क्योंकि गाय सनातन धर्म में पूजनीय मानी जाती है। क्षेत्र के लोगों ने इस पहल को आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया। दोनों समुदायों के लोगों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का सकारात्मक उदाहरण बताया।

सत्र की भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बने : विधानसभा अध्यक्ष

बरपेटा (हिंस)। असम विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने सत्र (मठ) की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो लोग सत्र की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, उन्हें स्वेच्छा से भूमि खाली कर देनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में केवल बेदखली ही नहीं, बल्कि कठोर कानून बनाकर उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। असम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद शनिवार को अपनी पत्नी के साथ बरपेटा सत्र पहुंचे रंजीत कुमार दास ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सत्र की भूमि पर अतिक्रमण असम की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सत्र भूमि पर अवैध कब्जे की स्थायी समस्या के समाधान के लिए कड़े कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अतिक्रमणकारियों को सजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने कहा कि सत्रों की भूमि और धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।

मणिपुर-म्यांमार से जुड़े ड्रग्स तस्करी कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है कछार

कछार (हिंस)। असम का कछार जिला अब नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम के रास्ते म्यांमार तथा अन्य पूर्वी देशों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का प्रमुख कॉरिडोर बनता जा रहा है। इसी कड़ी में कछार जिलांतर्गत लखीपुर थाना क्षेत्र में असम राइफल्स और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस मुख्यालय से आज जारी आधिकारिक बयान के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर अवैध एनडीपीएस पदार्थों के परिवहन को लेकर संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी लेने पर उनके पास से 10 हजार संदिग्ध याबा टैबलेट (करीब 1.072 किलोग्राम), संदिग्ध हेरोइन से भरे दो साबुनदानी (21 ग्राम) तथा तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार डीडी किट परीक्षण में बरामद सामग्री याबा और हेरोइन पाई गई। पूछताछ में आरोपितों ने खुलासा किया कि मादक पदार्थों की खेप मणिपुर से बराक नदी के रास्ते असम लाई जा रही थी। उनकी निशानदेही पर बराक नदी से एक मशीनयुक्त नाव भी बरामद कर जब्त की गई, जिसका उपयोग ड्रग्स परिवहन में किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जेम एल मालसॉम (27) तथा केन्यरोजर हमार (30), दोनों निवासी कांग्रेंगदोर गांव, फेरजावल जिला, मणिपुर के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई बराक घाटी में नदी मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय रास्तों के जरिए म्यांमार सीमा से आने वाले मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते नेटवर्क की ओर संकेत करती है।

मूल्यवृद्धि के विरोध में अमीनगांव में आसू का प्रदर्शन

रंगिया (विभास)। अत्यावश्यक खाद्य सामग्रियों के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों के विरोध में शुक्रवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के आह्वान पर अमीनगांव में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। ऑल कामरूप जिला छात्र संघ के तत्वावधान में अमीनगांव स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने यह विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कामरूप जिला छात्र संघ के प्रभारी अध्यक्ष सुरजीत कलिता और महासचिव तौफिकुर रहमान के नेतृत्व में निकाले गए इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के पचास से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सरकार विरोधी नारों से माहौल को गरमा दिया। विरोध कार्यक्रम में मौजूद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के

कार्यालय सचिव भवज्योति डेका ने सरकार की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के समय जनता को तरह-तरह के वादों से गुमराह कर सत्ता हासिल की। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद से ही आम जनता पर महंगाई का बोझ लादकर उन्हें बेहाल कर दिया गया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण आज आम जनता की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही मूल्यवृद्धि को कम नहीं किया गया, तो आसू इससे भी अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। दूसरी ओर, कामरूप जिला छात्र संघ के महासचिव तौफिकुर रहमान ने कहा कि अत्यधिक महंगाई के कारण आम जनता अब पूरी तरह टूट चुकी है। अगर सरकार ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण नहीं लगाया, तो आने वाले दिनों में जनता के सहयोग से इससे भी बड़ा और भयानक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आज के इस विरोध कार्यक्रम में ऑल कामरूप जिला छात्र संघ के सलाहकार गोलोक राजवंशी सहित जिले के विभिन्न हिस्सों से आए क्षेत्रीय छात्र संघों के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बस दुर्घटनाग्रस्त एक की मौत 45 घायल

जोरहाट (हिंस)। जोरहाट जिले के नाऊबेसा इलाके में नाइट सुपर बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 45 से अधिक लोग घायल हो गए । पुलिस ने शनिवार को बताया कि यात्रियों से भरा बस नाऊबेसा इलाके में अनियंत्रित होकर पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है । घटना के समय बस गुवाहाटी से माजुली के कमलाबाड़ी तक जा रही थी। पुलिस इस संबंध में दुर्घटना का एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन ने विद्यालय के बच्चों के बीच बांटी शिक्षण और खाद्य सामग्री

रंगिया (विभास)। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रंगिया शाखा द्वारा आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाखा के सदस्यों ने स्थानीय तीनाली स्थित जातीय विद्यालय प्रांगण में उपस्थित होकर छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और उनके बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। शाखा सदस्य मोनिका अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के 60 से अधिक छात्र-छात्राओं को पढ़ाई-लिखाई की सामग्रियां (स्टेशनरी) और खाद्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास

को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन की सदस्याओं ने विद्यालय परिसर में विभिन्न खेलकूद और प्रश्नोत्तरी (क्विज) का भी आयोजन किया। जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के सुप्रसिद्ध गीत *मायाविनी* के साथ हुआ। इसके बाद विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम का समापन सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के गायन के साथ किया गया। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष अरुणा अग्रवाल, सचिव संगीता सिकरिया सहित कई सदस्याएं उपस्थित रहीं। विद्यालय प्रबंधन ने मारवाड़ी महिला सम्मेलन की इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है।

अपोलो हॉस्पिटल्स गुवाहाटी ने स्पाइन केयर सर्जरी को मजबूत करने के लिए *फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी* प्रोग्राम लांच किया

गुवाहाटी। अपोलो हॉस्पिटल्स गुवाहाटी ने अपने *मिनिमली इनवेसिव स्पाइन सर्जरी प्रोग्राम* के तहत *फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी* लांच करके उन्नत स्पाइन केयर के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। यह पहल पूर्वोत्तर भारत में अपोलो की उन्नत स्पाइन केयर सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और यह विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के प्रति अस्पताल की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करती है। इस प्रेस मीट में वरिष्ठ न्यूरो और स्पाइन सर्जनों के साथ-साथ अपोलो हॉस्पिटल्स गुवाहाटी के अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में पीठ दर्द और रीढ़ से संबंधित विकारों के बढ़ते बोझ पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। विशेषज्ञों ने उन्नत उपचार विकल्पों की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया, जो मरीजों को तेजी से ठीक होने, कम दर्द, कम रक्तस्राव और रोजमर्रा के जीवन में जल्द वापसी सुनिश्चित करते हैं। *मोनोपोर्टल फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी* की शुरुआत के साथ, अपोलो हॉस्पिटल्स गुवाहाटी का उद्देश्य रीढ़ से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं-जिनमें पुराना पीठ दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका, स्पाइनल स्टेनोसिस और नर्व कम्प्रेशन शामिल हैं-के लिए व्यापक और विशेष उपचार प्रदान करना है। यह प्रोग्राम मुख्य रूप से *मिनिमली इनवेसिव* (न्यूनतम चीर-फाड़ वाली) सर्जिकल तकनीकों, तेजी से पुनर्वास और मरीजों के लिए बेहतर दीर्घकालिक परिणामों पर केंद्रित होगा। इस प्रेस मीट के दौरान एक ऐसी मरीज भी उपस्थित थीं, जिनकी पहले अपोलो हॉस्पिटल्स गुवाहाटी में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई थी; उन्होंने अपनी तेजी से रिकवरी और सर्जरी के परिणामों से मिली संतुष्टि के बारे में अपने अनुभव साझा किए। इस सत्र के दौरान, अपोलो हॉस्पिटल्स गुवाहाटी के वरिष्ठ न्यूरो और स्पाइन सर्जन डॉ. शमीम अहमद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आजकल पीठ के निचले हिस्से में दर्द एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या बन गई है। इसका मुख्य कारण अक्सर गलत जीवनशैली की आदतें, बैठने-उठने का गलत तरीका और कुछ मामलों में रीढ़ की हड्डी में लगी चोटें होती हैं। उन्होंने आगे इस बात पर भी जोर दिया कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उन्नत स्पाइन केयर सेवाओं की बढ़ती मांग के बावजूद, अभी भी बड़ी संख्या में मरीज विशेष उपचार के लिए इस क्षेत्र से बाहर (दूसरे शहरों में) जाते हैं। इस पहल के माध्यम से, अपोलो हॉस्पिटल्स गुवाहाटी का उद्देश्य उन्नत स्पाइन सर्जरी को अधिक सुलभ, किफायती और मरीजों के घर के नजदीक ही उपलब्ध कराना है, जिससे मरीजों को अस्पताल में कम समय बिताना पड़े और उन्हें किफायती दरों पर बेहतर इलाज मिल सके। इसी क्रम में, जाने-माने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन डॉ. गौरव चंबले ने *मोनोपोर्टल फुल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी* के विभिन्न लाभों और चिकित्सीय फायदों के बारे में विस्तार से बताया।

कामरूप जिले में *जन भागीदारी अभियान* के तहत विभिन्न विकास खंडों में स्वास्थ्य शिविर समेत जनसुनवाई और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रंगिया (विभास)। जनजातीय (आदिवासी) लोगों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से कामरूप जिले में *जन भागीदारी अभियान-सबसे दूर, सबसे पहले* कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास खंडों में व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कामरूप जिला प्रशासन की देखरेख में बोको, बोनगांव, बेजेरा और सुवालकुची विकास खंड के अंतर्गत विभिन्न *आदिसवा केंद्रों* में स्वास्थ्य शिविर, जन जागरूकता शिविर, ट्रांसेक्ट वॉक और जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अभियान के हिस्से के रूप में, बोको, बोनगांव, बेजेरा और सुवालकुची विकास खंड के तहत *आदिसवा केंद्रों* के माध्यम से विभिन्न गांवों को शामिल करते हुए शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में जनजातीय लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों और सेवाओं के संबंध में सहायता प्रदान की गई। बोको विकास खंड में 11 शिविरों के माध्यम से 47 गांवों को कवर किया गया, जहां 11 *आदिसवा केंद्रों* की मदद से कुल 905 लोग लाभान्वित हुए। बोंनगांव विकास खंड में 6 शिविरों के माध्यम से 11 गांवों को कवर किया गया और 11 *आदिसवा केंद्रों* की मदद से 455 लोग लाभान्वित हुए। बेजेरा विकास खंड में 1 शिविर के माध्यम से 1 गांव को कवर कर 3 *आदिसेवा केंद्रों* की मदद से 51 लोग और सुवालकुची विकास खंड में 2 शिविरों के माध्यम से 1 गांव को कवर कर 256 लोगों ने विभिन्न योजनाओं की सेवाओं और लाभों को प्राप्त किया। इस अभियान के दौरान पीएम उज्ज्वला योजना, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, अरुणोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), वन अधिकार पट्टा, पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, राशन कार्ड, जल

जीवन मिशन आदि विभिन्न योजनाओं से जुड़ी सेवाएं प्रदान की गईं। इसके अलावा, स्वास्थ्य जांच शिविरों के माध्यम से मधुमेह (डायबिटीज), उच्च और निम्न रक्तचाप, गैस्ट्राइटिस, एनीमिया (रक्तहीनता), ओरल कैंसर (मुंह का कैंसर), स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा (सर्विकल) कैंसर की स्क्रीनिंग और सामान्य स्वास्थ्य जांच भी की गई। गौरतलब है कि इस अभियान के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता बैठकें, ग्राम स्तर पर संवाद, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम भी लागू किए गए हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि जनजातीय लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। बोको विकास खंड के अंतर्गत कलियाबारी, भेहुआ, जारपारा, हाहीम एनसी, पुखुरीपारा, खातला, बरगांव, नामपथार, 1 नंबर शखाती और गोहालकोना आदिसेवा केंद्रों में 19 मई से 25 मई तक स्वास्थ्य शिविर और जन जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 20 मई को ट्रांसेक्ट वॉक और 21 मई से 23 मई तक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दूसरी ओर, बोंनगांव विकास खंड के अंतर्गत 1 नंबर रतनपुर, भेरभेरी एफवी, जलुकबारी, बालीजुरी, खाटिरा और कटाहबाड़ी बकरापाड़ा क्षेत्रों में निर्धारित समय सारणी के अनुसार स्वास्थ्य शिविर, जन जागरूकता शिविर, ट्रांसेक्ट वॉक और जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तरह, बेजेरा विकास खंड में मांदाकाटा के बरबाका एलपी स्कूल और होरुबाका आंगनवाड़ी केंद्र और रुद्रेश्वर स्थित फुलुंग एमई स्कूल आदि स्थानों पर इस अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच, जन जागरूकता और जनसुनवाई आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं, सुआलकुची विकास खंड के अंतर्गत बाथौगुड़ी आरनाई महिला समिति हॉल और शिलामहेखाइती में 19 मई से 23 मई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संपादकीय

क्या भारत प्रमुख अर्थव्यवस्था है?

प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के पद पर काम कर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के जिन संकेतों की व्याख्या की है, वे महज सवाल की आलोचना नहीं हैं, बल्कि बेहद गंभीर सवाल भी हैं। उन्होंने इस विरोधाभास को उठाया है कि भाजपा अपनी राजनीति के 'चरमोत्कर्ष' पर है। यकीनन बंगाल की चुनावी जीत ऐतिहासिक है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में वह हार रही है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर और निम्न है। इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि यह 'निम्नतम' श्रेणी में नहीं जाएगी। अर्थशास्त्री भल्ला के अनुसार, जीडीपी वृद्धि के लिहाज से भारत 9वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास में 8वें स्थान पर है और डॉलर में प्रति व्यक्ति विकास के संदर्भ में 16वें स्थान पर है। बांग्लादेश 8.3 फीसदी सालाना प्रति व्यक्ति विकास में प्रथम स्थान पर है। इथियोपिया जैसा युद्धरत और धूप से जले हुए चेहरों का देश 7.2 फीसदी जीडीपी वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। अमरीकी डॉलर में भारत का प्रति व्यक्ति विकास 4.7 फीसदी है और देश 16वें स्थान पर है। डॉ. भल्ला के इस डाटा के आधार पर सवाल सहज है कि भारत एक 'प्रमुख अर्थव्यवस्था' है अथवा आज भी 'नाजुक अर्थव्यवस्था' वाली श्रेणी में है? प्रख्यात अर्थशास्त्री की बुनियादी चिंता निजी-विदेशी निवेश (औसतन 32 फीसदी) और बीते सात सालों से 'रुपए' के लगातार अवमूल्यन को लेकर है। निर्यात भी बहुत कम हो गया है। दूसरा विश्लेषण प्रो. संतोष मेहरोत्रा का है। वह भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के 'विकासवादी अर्थशास्त्री' हैं। 2009-14 के दौरान वह योजना आयोग में 'अनुप्रयुक्त मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान' के महानिदेशक (भारत सरकार में सचिव पद के समकक्ष) रहे। आज भी ब्रिटेन, मॉस्को समेत कुछ विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। प्रो. मेहरोत्रा ने शोधात्मक विश्लेषण किया है कि भारत में करीब 12.10 करोड़ युवा न तो पढ़ रहे हैं और न ही काम कर रहे हैं। उनमें से करीब 8 करोड़ युवा अपना रोजगार 'कृषि' बताते हैं, जो उनका पुश्तैनी काम होगा। इतना व्यापक, युवा श्रम बेकार जा रहा है, क्योंकि वे बेरोजगार हैं। यह देश के लिए शर्मनाक और विडंबनापूर्ण स्थिति है। प्रो. मेहरोत्रा के मुताबिक, 2012-25 के दौरान बेरोजगारी दर 'तिगुनी' बढ़ चुकी है। सरकार कुछ भी दावे करती रहे। खुदरा महंगाई दर भी 5 फीसदी को पार कर चुकी है और अभी महंगाई तेजी से बढ़ेगी। यह देश की व्यवस्था की विडंबना है कि मौजूदा दौर में कामगार या दिहाड़ीदार अथवा स्वरोजगार में लगे लोगों की आमदनी नहीं बढ़ सकी है, तो वे तबके महंगाई का सामना कैसे कर पाएंगे? दरअसल अर्थव्यवस्था संबंधी विरोधाभास यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी पांच देशों के प्रवास से लौटे हैं। इस दौरान भारत के साथ 57 करार किए गए हैं। प्रधानमंत्री 50 से अधिक वैश्विक सीईओ से भी मिले। आज यूरोपीय संघ के केंद्र में भारतीय बाजार और अर्थव्यवस्था है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जनवरी, 2026 में भारत और यूरोपीय संघ में 'मुक्त व्यापार समझौता' किया गया। हस्ताक्षर भी किए गए। शीत युद्ध के कालखंड में ऐसा शुरू नहीं था। पश्चिम के साथ भारत के अंतरंग, रणनीतिक, मधुर संबंध नहीं थे, क्योंकि हम तत्कालीन सोवियत संघ की रक्षा और आर्थिक नीतियों के अनुसार ही निर्णय लेते थे। आज भारत का निर्यात बाजार और यूरोप के साथ पूंजी, विकसित प्रौद्योगिकी, ग्रीन ऊर्जा, एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स, रक्षा, बुनियादी ढांचे, सांस्कृतिक, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान, निवेश आदि क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारियों ने भारत को 'धुरी' बना दिया है। यदि यूरोपीय देशों ने भारत के साथ इतने करार किए हैं, तो भारत आर्थिक रूप से सक्षम होगा और विशालतम बाजार होगा। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स जैसे देश और नॉर्डिक देश भी भारत के साथ अंतरंग और गहरे रणनीतिक संबंध बना रहे हैं, तो यह भारत की ताकत का ताकत है। चीन से संभावित जोखिमों को कम करने के लिए भी यूरोप भारत को साझेदार बना रहा है। क्या भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण ये रणनीतिक साझेदारियां संभव थीं? लिहाजा एक बार फिर प्रधानमंत्री को देश को संबोधित कर खुलासा करना चाहिए कि सच क्या है? भारत की दृष्टि से दूसरे देशों के साथ आर्थिक समझौते तभी लाभदायक माने जाएंगे, अगर निर्यात के बजाय आयात कम हो। निर्यात और आयात के बीच संतुलन पैदा करने की जरूरत है।

अर्थशास्त्री भल्ला के अनुसार, जीडीपी वृद्धि के लिहाज से भारत 9वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास में 8वें स्थान पर है और डॉलर में प्रति व्यक्ति विकास के संदर्भ में 16वें स्थान पर है। बांग्लादेश 8.3 फीसदी सालाना प्रति व्यक्ति विकास में प्रथम स्थान पर है। इथियोपिया जैसा युद्धरत और धूप से जले हुए चेहरों का देश 7.2 फीसदी जीडीपी वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। अमरीकी डॉलर में भारत का प्रति व्यक्ति विकास 4.7 फीसदी है और देश 16वें स्थान पर है। डॉ. भल्ला के इस डाटा के आधार पर सवाल सहज है कि भारत एक 'प्रमुख अर्थव्यवस्था' है अथवा आज भी 'नाजुक अर्थव्यवस्था' वाली श्रेणी में है? प्रख्यात अर्थशास्त्री की बुनियादी चिंता निजी-विदेशी निवेश (औसतन 32 फीसदी) और बीते सात सालों से 'रुपए' के लगातार अवमूल्यन को लेकर है। निर्यात भी बहुत कम हो गया है। दूसरा विश्लेषण प्रो. संतोष मेहरोत्रा का है। वह भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के 'विकासवादी अर्थशास्त्री' हैं। 2009-14 के दौरान वह योजना आयोग में 'अनुप्रयुक्त मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान' के महानिदेशक (भारत सरकार में सचिव पद के समकक्ष) रहे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों की रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला "आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर" अभी भी बहुत अधिक है

जनस्वास्थ्य पर बाजार का बढ़ता कब्ज़ा

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केवल चिकित्सा सेवा का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का विषय भी है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर से मापी जाती है। यदि समाज का बड़ा हिस्सा उपचार, दवाइयों, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाए, तो आर्थिक विकास के दावे खोखले साबित होते हैं। दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में भारत सहित विश्व के अनेक देशों में स्वास्थ्य क्षेत्र का तेजी से बाजारीकरण हुआ है। स्वास्थ्य सेवा, जो मूलतः मानव अधिकार मानी जानी चाहिए थी, धीरे-धीरे लाभ कमाने वाले उद्योग में बदलती चली गई। निजी अस्पतालों, महंगी दवाओं, बीमा-आधारित उपचार और कॉरपोरेट चिकित्सा व्यवस्था ने आम नागरिक, विशेषकर गरीब और ग्रामीण वर्ग, को स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर कर दिया है। ऐसे समय में भारतीय राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करे और जमीनी स्तर तक उसकी पहुँच सुनिश्चित करे। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या असमानता है। महानगरों में अत्याधुनिक अस्पताल और सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयाँ और उपकरण नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारत में स्थिति यह है कि लाखों लोग केवल आर्थिक अभाव के कारण उपचार नहीं करा पाते। निजी अस्पतालों का खर्च इतना अधिक है कि एक गंभीर बीमारी पूरे परिवार को गरीबी में धकेल सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों की रिपोर्टें बताती हैं कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला "आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर" अभी भी बहुत अधिक है। इसका अर्थ है कि लोगों को इलाज का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से देना पड़ता है। यही बाजारीकरण का सबसे खतरनाक परिणाम है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए सबसे पहले राज्य को प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होगा। भारत के गाँवों और छोटे कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन अधिकांश केंद्रों में डॉक्टरों की कमी, दवाइयों का अभाव, खराब भवन और उपकरणों की कमी जैसी समस्याएँ बनी रहती हैं। सरकार को स्वास्थ्य बजट में पर्याप्त वृद्धि करके इन संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नियमित डॉक्टर, प्रशिक्षित नर्सें, लैब सुविधाएँ और आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराना अनिवार्य होना चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर पर ही रोगों की पहचान और उपचार संभव हो जाए, तो बड़े अस्पतालों पर दबाव कम होगा और गरीब लोगों को शहरों की ओर पलायन नहीं करना

पड़ेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। केवल जिला अस्पतालों पर निर्भर रहने से दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकारों को पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेवाएँ और सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को मजबूत बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और प्राथमिक उपचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। यदि इन कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रशिक्षण, सम्मानजनक वेतन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो वे स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर तक पहुँचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक का उपयोग भी जमीनी स्तर पर पहुँच बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी व्यवस्थाएँ दूरदराज क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती हैं। भारत में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों का पहुँचना कठिन है। ऐसे क्षेत्रों में ऑनलाइन परामर्श और डिजिटल डायग्नोस्टिक सेवाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। हालांकि तकनीक को मानव संपर्क का विकल्प नहीं, बल्कि सहयोगी माध्यम के रूप में विकसित करना होगा। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति भी जरूरी है ताकि कम साक्षरता वाले लोग भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। सस्ती और सार्वभौमिक दवा उपलब्धता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य विस्तार का एक आवश्यक पहलू है। निजी बाजार में दवाइयों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। राज्य को जनऔषधि केंद्रों का विस्तार करना चाहिए और आवश्यक दवाओं की मूल्य-नियंत्रण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त या अत्यंत सस्ती दवाओं की उपलब्धता स्वास्थ्य असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में आवश्यक जाँच सुविधाएँ और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि लोगों को निजी प्रयोगशालाओं और मेडिकल स्टोरों पर निर्भर न रहना पड़े। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मानव संसाधन की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भारी कमी बनी रहती है क्योंकि अधिकांश चिकित्सक शहरी क्षेत्रों में कार्य करना पसंद करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, सरकार को ग्रामीण सेवा को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ बनानी चाहिए। मेडिकल छात्रों के लिए ग्रामीण सेवा अनिवार्य करना, बेहतर वेतन, आवास और सुरक्षा सुविधाएँ देना तथा स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा में अवसर प्रदान करना उपयोगी कदम हो सकते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय से जुड़े डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तैयार किए जाएँ, तो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिरता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ेंगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवारक स्वास्थ्य देखभाल को भी प्राथमिकता देनी होगी। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी रोग होने के बाद उपचार पर अधिक केंद्रित है, जबकि स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश अपेक्षाकृत कम है। यदि राज्य स्वच्छ पेयजल, पोषण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसी योजनाओं को मजबूत करे, तो अनेक बीमारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सकता है। यह न केवल लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर आर्थिक बोझ भी कम करेगा। राज्य को निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के नियमन में भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। निजी अस्पतालों की मनमानी फीस, अनावश्यक जाँच और व्यावसायिक शोषण आम समस्या बन चुकी है। कई बार मरीजों की मजबूरी को लाभ कमाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार को एक मजबूत नियामक ढांचा विकसित करना चाहिए जो उपचार शुल्क, दवाइयों की कीमत और चिकित्सा नैतिकता की निगरानी कर सके। स्वास्थ्य सेवा को केवल बाजार के भरोसे छोड़ देना लोकतांत्रिक राज्य की जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसा होगा। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना भी जरूरी है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीब परिवारों को राहत प्रदान की है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोग इनके दायरे से बाहर हैं। कई बार बीमा योजनाएँ केवल अस्पताल आधारित उपचार तक सीमित रह जाती हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ केवल उपचार नहीं, बल्कि रोकथाम, पोषण और प्राथमिक देखभाल को भी शामिल करें। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को संतुलित और पारदर्शी बनाना होगा। निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग उपयोगी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक हित सर्वोपरि रहना चाहिए। यदि लाभ कमाना ही प्राथमिक उद्देश्य बन जाए, तो गरीब और कमजोर वर्ग फिर से हाशिए पर चले जाएँगे।

स्वास्थ्य सेवा, जो मूलतः मानव अधिकार मानी जानी चाहिए थी, धीरे-धीरे लाभ कमाने वाले उद्योग में बदलती चली गई। निजी अस्पतालों, महंगी दवाओं, बीमा-आधारित उपचार और कॉरपोरेट चिकित्सा व्यवस्था ने आम नागरिक, विशेषकर गरीब और ग्रामीण वर्ग, को स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर कर दिया है। ऐसे समय में भारतीय राज्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करे और जमीनी स्तर तक उसकी पहुँच सुनिश्चित करे। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या असमानता है। महानगरों में अत्याधुनिक अस्पताल और सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पर्याप्त डॉक्टर, दवाइयाँ और उपकरण नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

देश | दुनीया से

मानसिक सेहत के लिए मनोविज्ञान शिक्षा जरूरी

वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जीवन के तनाव, दबाव, संघर्ष, परेशानी, असफलता, नौकरी की चिंता, वैवाहिक जीवन की असफलता, अति महत्वाकांक्षा तथा अव्यक्त भय से गुजर रहा है। वैसे तो मनोरोग, अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय विशेषज्ञों तथा मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों के व्यावसायिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ही डिप्रैशन, एंग्जायटी, मेंटल ट्रॉमा यानी मानसिक आघात, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तथा सीजोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का मानसिक, भावनात्मक और चिकित्सीय पहचान, निदान और उपचार करने के लिए अधिकृत होते हैं, लेकिन कोई भी शिक्षित तथा जागरूक व्यक्ति ऐसे मनोरोगी के सामान्य लक्षणों को पहचान कर उसे मनोविज्ञान चिकित्सक तक पहुंचा सकता है। परिवार तथा समाज में शिक्षित तथा जागरूक व्यक्तियों की सहायता से अवसादग्रस्त मनोरोगियों को सकारात्मक मार्गदर्शन से बचाया जा सकता है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति असफलताओं, विफलताओं, अति महत्वाकांक्षाओं, अपेक्षाओं, उपेक्षाओं, जीवन की पेचीदगियों, देनदारियों, भय तथा शोक से ग्रसित है और कमजोर है। व्यक्ति मानसिक अवसाद तथा मनोरोग के दलदल में फंसता ही चला जाता है। व्यक्ति को यह पता ही नहीं चलता कि वह कब अवसादग्रस्त हो गया है। जिसका आत्मबल कमजोर है, वह कभी भी भांग, शराब, चिट्टा रासायनिक तथा मादक पदार्थों के चक्कर में फंस सकता है। मादक पदार्थों के सेवन से वह कुछ समय के लिए दबाव तथा चिंतामुक्त हो जाता है। नशे के लिए शुरू होती है चोरी, डकैती, ठगी, मांगने की वृत्ति, मारपीट, घरेलू हिंसा। जिससे उसकी पारिवारिक तथा सामाजिक छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बैंकों के कर्ज, लोगों का उधार, कुर्की होना, भयग्रस्त होना तथा कोई भी अच्छा न होने के संकेत में वह गम्भीर अवसाद की स्थिति में चला जाता है। मनोरोगी व्यक्ति को यह लगता है कि अब उसका कोई नहीं है, वह अकेला है, अन्दर से टूट चुका है और वह परिवार व समाज के लिए बोझ है। अब उसके जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं है। चारित्रिक, शारीरिक, पारिवारिक तथा सामाजिक पतन होने पर जब उसे कुछ भी नहीं सूझता तो वह आत्महत्या, आत्म-वध, आत्म

विनाश तथा खुदकुशी का विकल्प ढूंढता है। आज प्रतिदिन आत्महत्या के बहुत से मामले सामने आ रहे हैं। अभावग्रस्त ही नहीं बल्कि प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चे, युवा, अधेड़ तथा वृद्ध महिला और पुरुष भी अक्षम और असहाय पाकर क्षण भर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं जो कि बहुत चिंतनीय तथा विचारणीय है। आज सामान्य जीवन में अधिकतर लोग अपने कार्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के युवा तथा पाठशालाओं के अल्पायु के बच्चे भी दबाव, तनाव तथा मानसिक अवसाद जैसे दंश को झेल रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक अवसाद जैसे अति गम्भीर विषयों को सामान्य समझ कर प्राथमिकता नहीं दी जाती। शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत ही गम्भीर और संवेदनशील विषय है। परिवार, समाज तथा शिक्षण संस्थान इस विषय पर सामान्य ज्ञान और सकारात्मकता से मनोरोगी का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। जब व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं पाता तब वह सही व गलत का निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ पाकर ऐसा आत्मघाती कदम उठाता है। ऐसे व्यक्तियों का मनोबल तथा आत्मबल बहुत ही कमजोर होता है तथा वे निराशा एवं नकारात्मकता से भरे होते हैं। इनका आम व्यवहार सामान्य न होकर अव्यावहारिक तथा असंतुलित होता है। पारिवारिक दृष्टि से आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों के आचार, व्यवहार, वार्तालाप, क्रोध तथा चिड़चिड़ेपन पर निरंतर नजर रखी जाए। उनके साथ बहुत ही संवेदनशील व्यवहार अपेक्षित होता है। अवसाद ग्रस्त लोगों को लगता है कि इनकी परिवार तथा समाज में कोई सुनने और समझने वाला नहीं है। ये लोग अपने आप को असहाय, असुरक्षित, बेकार और अकेला समझते हैं। सामाजिक अलगाव भी अवसाद का एक मुख्य कारण है। इसलिए इन लोगों को अकेलापन पसंद होता है। लगातार पैसों की तंगी, कर्ज, बेरोजगारी, खाने-पीने, घर की सामान्य आवश्यकताएं पूरी न होना, रोग के ईलाज के लिए पैसे न होना, भविष्य की चिंता जैसे लम्बे समय से दबाव और तनाव से ये लोग अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त नींद पूरी न होना तथा रोगग्रस्त होना, बैंक बैलेंस बिगडना, कुर्की होना, असफल होने का डर, बेरोजगारी, प्रेम सम्बन्ध टूटना, कम्पनी डूबना, नौकरी से निकाल देना, परीक्षा में असफलता, रिश्ता टूटना, बदनामी, इमेज खराब होने का डर भी अवसाद के मुख्य कारण पाए जाते हैं। इसलिए वर्तमान में बड़े-बड़े अधिकारी, धनवान, कारपोरेट, उद्योगपति, व्यवसायी, कांट्रैक्टर, राजनेता, अभिनेता, डॉक्टर तथा इंजीनियर जैसे सफल व्यक्ति भी आत्महत्या करते देखे गए हैं। सब कुछ होने के बावजूद उन्हें लगता है कि उनका कोई नहीं है, वे अकेले जीवन चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये लोग बस क्षण भर में ही आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। आवश्यक यह है कि परिवार तथा समाज में यदि किसी की पढ़ाई में गिरावट, स्कूल, कालेज तथा आफिस न जाना, दोस्तों से कट जाना, अकेले रहना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, डरना, रोना, चुप रहना, नींद या भूख न लगना तथा 'मैं बेकार हूं, मेरा कोई नहीं है' जैसी बातें करने के लक्षण दिखें तो सचेत हो जाएं और ऐसे व्यक्तियों से संवेदनशील होकर सकारात्मक व्यवहार करें। परिजनों को इस तरह के लक्षण दिखते ही बिना समय गंवाए मनोरोग चिकित्सक से सलाह और उपचार करवाना चाहिए। मानसिक अवसाद ग्रस्त रोगियों को अकेला नहीं छोडना चाहिए।

कुछ | अलग

वक्त-बेवक्त आम भी हो जाते हैं खास

आम के मौसम में आम की बात न हो तो ठीक नहीं लगेगा। वैसे भी चिंतक मानते हैं कि आम अक्सर तिरस्कार झेलता रहा है। इसलिए आम की खुलकर बात तो होना चाहिए। आम की बात कोई ख़ास करे तो और भी अच्छा। तभी आम के हक़ में बात बनती है। वरना आम आम ही रहता है। देखा जाए तो आम और ख़ास में ज़मीनी अंतर नहीं होता। आम आम होता है और ख़ास ख़ास। आम की बदौलत कुछ आम ख़ास बन जाया करते हैं। पर मुश्किल यह होती है कि आम जब ख़ास बन जाता है तो आम को भूल जाता है। आम को ख़ास के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। बहरहाल, यहां बात मौसमी आम की हो रही है। सो यह बता देना लाज़िमी है कि यह मौसम आम के लिए मुफ़ीद रहता हुआ प्रतीत होता है। आम खूब फले-फूले। रास्तों के किनारे यों ही उग आए आम के पेड़ आमों से लद गए। इस मौसम में न केवल वोट पड़े, बल्कि पानी की बूंदें भी पड़ती रहीं। वोट और पानी का असर आमों पर एक-सा हुआ करता है। उनमें मिठास आ जाती है। भले ही बीते वर्षों में उनकी किसी ने खोज-खबर न ली हो, लेकिन इस बार कुछ राज्यों में उनकी टूटकर पूछ-परख हुई। जमकर सेवादारी हुई। माहौल तो आंधियों का भी बार-बार बनता रहा है! बारिश के साथ चुनावी आंधी भी चली। आंधी में कुछ कमजोर आम टूट गए। उन्हें काट-पीटकर अपने पक्ष में तैयार कर लिया गया, 'आम काट के खा रहा हूं मैं, क़त्ल-ए-आम मचा रहा हूं मैं।' अनेक आम उलटे लटके हुए शीर्षासन करते रहे। आंधी में अपने आप को गिरने से बचाने की क़वायद में जुटे रहे। कमज़ोर शाखों के कमज़ोर आमों का शोषण करते हुए गदरा गए।

आप का | नजरीया

आईएसआई की जासूस ज्योति मल्होत्रा

हरियाणा और पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की आईएसआई को खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में जिन लोगों को हाल ही में गिरफ्तार किया है, उनमें हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप से वुछ संदिग्ध साम्ग्रियां मिली हैं। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीव्रेटस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता धारा-152 के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद से ही ज्योति की पाकिस्तान यात्रा की काफी चर्चा हो रही है। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पन्नों का नाम ट्रैवल विद जो चला रही हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 3.79 लाख से ज्यादा सब्स्व्राइबर हैं और इंस्टा पर 1.40 लाख फालोअर्स हैं। उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों में अपनी यात्रा के वीडियोज से लेकर अपनी विदेश यात्रा के कई वीडियो पोस्ट किए हैं। ज्योति की गिरफ्तारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े जासूसी नेटवर्व के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तेज करने के नतीजे से हुई है। दावा किया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां एसेट के तौर पर तैयार कर रही थी। ज्योति पर कई तरह के आरोप लगे हैं। वैसे वो पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्व में आई और आगे क्या हुआ यह सब डिटेलस मीडिया में आ चुकी है। उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। काम की बात यह है कि पाक खुफिया एजेंसियों से भी संपर्व में थी और यहां तक दावा किया जा रहा है कि उन्होंने आपरेशन सिंदूर की भी खुफिया जानकारी पाक को पहुंचाई। हिसार के एसपी शशांक वुमार सवान ने रविवार को बताया कि ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात अधिकारी दानिश उर्प एहसान-उर-रहीम के संपर्व में थी। यह संपर्व 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत-पाक के चार दिवसीय सैन्य तनाव के बाद भी बना रहा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ज्योति के पास सैन्य जानकारी तक सीधी पहुंच थी या नहीं लेकिन पाकिस्तान इंटेलीजेंस आपरेशन के भी सीधे संपर्व में थी। एफआईआर के अनुसार 2023 में पाकिस्तानी वीजा के लिए आवेदन करते समय वह दानिश के संपर्व में आई थी। ज्योति ने दो बार पाकिस्तान और चीन की एक बार यात्रा की। पीटीआई के अनुसार हिसार एसपी का कहना है कि ज्योति पीआईओ के संपर्व में थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और अपने वंटेंट के जरिए पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने के लिए वहां के हैंडलर्स से सीधे संपर्व में रहने का आरोप है। ज्योति के पिता हरीश वुमार ने बीबीसी को बताया कि पुलिस अधिकारी गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे आए और ज्योति को अपने साथ ले गए। पांच-छह लोग आए और आधे घंटे तक घर की तलाशी ली। जिसके बाद तीन मोबाइल और लैपटॉप धर लिया। उन्होंने कहा मेरी बेटी सरकार की अनुमति से पाकिस्तान गईं थी। उसकी जांच भी की गई और फिर से वीजा दिया गया जिसके बाद वह पाकिस्तान गईं थी। रिपोर्ट के अनुसार ज्योति के मोबाइल फोन में पाकिस्तान उच्चायोग के कई अधिकारियों के नंबर मिले हैं। जिनसे वह निरंतर संपर्व में रहती थी और देश की महत्वपूर्ण जानकारी और सूचनाएं उन तक पहुंचा रही थी। हैरान करने वाली बात यह है कि वह देश भक्ति का लबादा ओढ़कर अपनी करतूतों को अंजाम दे रही थी। इन लोगों की गिरफ्तारियां भारतीय एजेंसियों की बहुत बड़ी सफलता है। पर जरूरी है कि ज्योति जैसे पाकिस्तानी एसेट्स को पूरे नेटवर्व को जड़ से खत्म किया जाए। उन लोगों तक भी पहुंचा जाए जिसमें ये लोग संपर्व में थे।

हरियाणा पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप से वुछ संदिग्ध सामग्रियां मिली है। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीव्रेटस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता धारा-152 के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद से ही ज्योति की पाकिस्तान यात्रा की काफी चर्चा हो रही है। ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पन्नों का नाम ट्रैवल विद जो चला रही हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 3.79 लाख से ज्यादा सब्स्व्राइबर हैं और इंस्टा पर 1.40 लाख फालोअर्स हैं। उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों में अपनी यात्रा के वीडियोज से लेकर अपनी विदेश यात्रा के कई वीडियो पोस्ट किए हैं। ज्योति की गिरफ्तारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े जासूसी नेटवर्व के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तेज करने के नतीजे से हुई है। दावा किया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों एसेट के तौर पर तैयार कर रही थी। ज्योति पर कई तरह के आरोप लगे हैं। वैसे वो पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्व में आई और आगे क्या हुआ यह सब डिटेलस मीडिया में आ चुकी है। उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। काम की बात यह है कि पाक खुफिया एजेंसियों से भी संपर्व में थी और यहां तक दावा किया जा रहा है कि उन्होंने आपरेशन सिदूर की भी खुफिया जानकारी पाक को पहुंचाई। हिसार के एसपी शशांक वुमार सवान ने रविवार को बताया कि ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात अधिकारी दानिश उर्प एहसान-उर-रहीम के संपर्व में थी। यह संपर्व 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत-पाक के चार दिवसीय सैन्य तनाव के बाद भी बना रहा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ज्योति के पास सैन्य जानकारी तक सीधी पहुंच थी या नहीं लेकिन पाकिस्तान इंटेलीजेंस आपरेशन के भी सीधे संपर्व में थी।

दृष्टि | कोण

तारीख पर तारीख से मुक्ति की पहल

न्याय के गलियारों में गूंजती 'तारीख पर तारीख' की प्रतिध्वनि दरअसल उस आम आदमी की सिसकी है, जिसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता फाइलों के बोझ तले दम तोड़ रही है। फिल्म 'दामिनी' का वह मशहूर संवाद– 'तारीख पर तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला' महज एक फिल्मी लाइन नहीं, बल्कि भारत की अदालतों की उस कड़वी हकीकत का जीवंत दस्तावेज़ है, जिससे हर रोज देश का आम नागरिक गुज़रता है। 'न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना है'—यह कहावत भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी चुनौती रही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विसंगति को जड़ से मिटाने के लिए एक क्रांतिकारी पहल की है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने स्पष्ट किया है कि जमानत याचिकाओं में अनावश्यक देरी न केवल कानूनी विफलता है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' के ऐतिहासिक मामले में स्थापित यह सिद्धांत कि 'कानूनी प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए', आज भी हमारी न्यायिक शुचिता की कसौटी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे बड़े न्यायालयों में संसाधनों की भारी कमी और न्यायिक ढांचे पर अत्यधिक दबाव चिंताजनक है, जहां एक न्यायाधीश को प्रतिदिन औसतन 200 जमानत याचिकाओं की सुनवाई करनी पड़ती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार जायसवाल ने 'तारीख पर तारीख' की संस्कृति पर तीखी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि इस न्यायिक देरी का अनुचित लाभ उठाकर कई दागी व्यक्ति राजनीति के शीर्ष पदों तक पहुंच जाते हैं। न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि देरी के लिए केवल न्यायपालिका ही नहीं, बल्कि पुलिस द्वारा समय पर फोरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों को पेश न करना भी समान रूप से जिम्मेदार है।

कानूनी परिप्रेक्ष्य में 'स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बालचंद (1977)' के तहत जस्टिस कृष्ण अय्यर का यह सिद्धांत सर्वोपरि है कि 'जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद'। भारतीय न्यायशास्त्र के अनुसार जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष है। इसके बावजूद, 'तारीख पर तारीख' के चक्रव्यूह में फंसकर विचाराधीन कैदी बिना किसी अपराध के वर्षों जेल में काट देते हैं। इसी न्यायिक जड़ता को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब जमानत मामलों को हर हफ्ते या अधिकतम दो हफ्ते में लिस्ट करने का निर्देश दिया है। 'सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022)' मामले में भी अदालत ने साफ कहा था कि जमानत में देरी नागरिक की गरिमा पर सीधी चोट है। विकसित देशों में जमानत प्रक्रिया भारत की तुलना में अधिक त्वरित और तकनीक-केंद्रित है। यूनाइटेड किंगडम में 'बेल एक्ट 1976' के तहत जमानत एक वैधानिक अधिकार है, जिस पर अदालतें कुछ ही घंटों या दिनों में निर्णय लेती हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका में 'एक्चुअरियल रिस्क असेसमेंट' और एल्गोरिदम जैसे तकनीकी टूल्स का उपयोग न्यायाधीशों को वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने और प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। इसी दिशा में भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी अब 'ऑटोमेटिक लिस्टिंग सिस्टम' पर जोर दे रहा है। इस न्यायिक जड़ता को तोड़ने के लिए 'मद्रास उच्च न्यायालय' की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय मॉडल बनाना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु 'विशेष जमानत अदालतें' या समर्पित 'स्वतंत्रता बेंच' का गठन समय की मांग है। सुधार का दूसरा अनिवार्य स्तंभ 'संस्थागत जवाबदेही' है।

कांग्रेस हताश होकर प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी कर रही : गिरीश चंद्र यादव

जौनपुर (हिंस)। यूपी के जौनपुर में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह हताश हो चुकी है और प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संसदीय मर्यादा का पालन आवश्यक है। असंसदीय भाषा का प्रयोग निंदनीय है। खेल मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी लगातार असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तब बिहार की जनता ने चुनाव में उसका जवाब दिया था।

रेल मंत्री ने जयपुर में 420 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र

बोले, रेलवे में जल्द 1.78 लाख भर्तियां

जयपुर (हिंस)। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को जयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने जयपुर स्थित कॉन्सटीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया और विभिन्न केंद्रीय विभागों में चयनित 420 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे में जल्द ही एक लाख 78 हजार पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। रोजगार मेले के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे में भर्ती प्रक्रिया को अब अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है। पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थीं, लेकिन अब वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू होने से युवाओं को पहले से जानकारी मिल रही है कि किस समय कौन-सी भर्ती निकलेगी। उन्होंने बताया कि रेलवे भर्ती प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया गया है। पहले क्वार्टर में लोको पायलट, दूसरे क्वार्टर में टेक्निशियन एवं अन्य तकनीकी पदों, तीसरे क्वार्टर में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जैसे

स्टेशन मास्टर और जूनियर इंजीनियर तथा चौथे क्वार्टर में लेवल-1 पदों के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। इससे युवाओं को बेहतर तैयारी और नियमित अवसर मिल रहे हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान में रेलवे विस्तार योजनाओं की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे देशभर में 36 हजार किलोमीटर नए ट्रैक बिछाने पर कार्य कर रही है। राजस्थान में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद राज्य में लगभग 200 नई ट्रेनें चलाने की योजना है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बाद राजस्थान को 50 से अधिक नई ट्रेनें दी जा चुकी हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवा और उनके परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में रेल मंत्री ने युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें देश निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, लोकसभा सांसद मंजू शर्मा तथा विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद रहे। देशभर के 47 स्थानों पर आयोजित इस रोजगार मेले का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने एक साथ 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेले के माध्यम से रेलवे, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, डाक विभाग समेत विभिन्न केंद्रीय विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गईं।

जाम, नशा और अवैध खनन पर आवाज उठाना पड़ा भारी, युवक ने लगाई सुरक्षा की गुहार

किशनगंज (हिंस)। जिले के ठाकुरगंज निवासी अमित राज यादव ने अवैध बालू खनन और भारी वाहनों के परिचालन के खिलाफ आवाज उठाने के बाद खुद और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग जिला प्रशासन से की है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अमित राज यादव ने अपने आवेदन में कहा है कि उन्होंने 5 मई 2026 को ठाकुरगंज थाना परिसर में आयोजित पुलिस-पब्लिक संवाद कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के समक्ष अवैध बालू खनन, नो-एंट्री के दौरान भारी मालवाहक वाहनों के परिचालन, जाम की समस्या, स्कूली बच्चों को हो रही परेशानी तथा नशा मुक्ति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि शिकायत के बाद बालू घाट संचालकों से जुड़े कथित लोगों और गुर्गों द्वारा उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं तथा उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है। इस कारण उनके परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। अमित राज यादव ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध

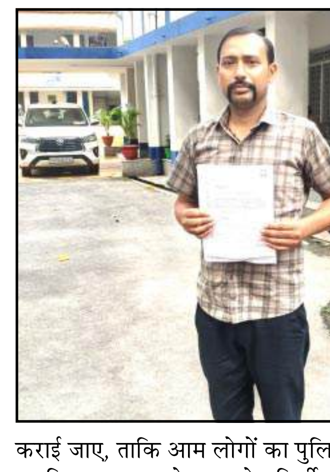

कराई जाए, ताकि आम लोगों का पुलिस और प्रशासन पर विश्वास बना रहे तथा लोग निर्भीक होकर जनहित के मुद्दे उठा सकें। पुलिस अधीक्षक को दिए एक अन्य आवेदन में उन्होंने ठाकुरगंज नगर में जाम और नशे की बढ़ती समस्या की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि शिव मंदिर के समीप जैन धर्मशाला से कृष्णापुरी मुख्य सड़क तक टोटो, पिकअप और भारी वाहनों के कारण लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। साथ ही नगर में स्मैक और शराब जैसे नशे के बढ़ते प्रचलन तथा चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है।

श्रमिक राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति, उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ (हिंस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को और व्यापक तथा परिणामोन्मुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, *सेवामित्र व्यवस्था* को और प्रभावी बनाने, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जाए और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना भी तैयार की जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत आठ से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में योजना 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने *सेवामित्र व्यवस्था* को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी तथा जनोपयोगी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 से संचालित इस व्यवस्था के तहत नागरिक मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल अथवा कॉल सेंटर के माध्यम से घरेलू सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में पोर्टल पर 1097 सेवा प्रदाता, 5049 सेवामित्र और 54 हजार 747 कुशल कामगार पंजीकृत हैं। मुख्यमंत्री

ने सरकारी विभागों में भी आवश्यकता के अनुसार सेवामित्र व्यवस्था के उपयोग के प्रस्ताव को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के अनुकूल वातावरण और श्रमिक हितों के बीच संतुलन बनाना सरकार की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 32 हजार 583 कारखाने पंजीकृत हो चुके हैं। मार्च 2017 तक जहां यह संख्या 14 हजार 176 थी, वहीं अप्रैल 2017 के बाद 18 हजार 407 नए कारखानों का पंजीकरण हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4860 कारखानों का पंजीकरण किया गया। विभाग को बीआरएपी सुधारों के क्रियान्वयन में *टॉप अचीवर* के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है तथा उद्योग समागम 2025 में श्रम क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी *लेबर अड्डों* को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों को केवल श्रमिकों के एकत्रीकरण स्थल के रूप में नहीं, बल्कि श्रमिक सहायता एवं सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में दूसरे क्षेत्रों से आने वाले श्रमिकों के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित आवास सुविधा उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्रस्तावित औद्योगिक श्रमिक प्रशिक्षण संस्थान और छात्रावास योजना को कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना समय की मांग है। बैठक में बताया गया कि विष्णुपुरी स्थित भूमि पर 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है, जहां कारपेंटरी, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लंबर, पेंटर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सहित विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेनाझाबर स्थित भूमि पर 200 प्रशिक्षुओं की क्षमता वाला छात्रावास भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में बताया गया कि जुलाई 2025 में गठित *उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन* के माध्यम से युवाओं को देश और विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। रोजगार मिशन को विदेश मंत्रालय से भर्ती एजेंसी का लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में आयोजित रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से 27 हजार 555 युवाओं का चयन किया गया, जिनमें 2300 युवाओं का चयन विदेशों में रोजगार हेतु हुआ। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश में 3030 रोजगार मेलों और कैंपस प्लेसमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से तीन लाख 74 हजार 776 अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इसी अवधि में आयोजित 4873 कॅरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों में छह लाख 80 हजार 469 युवाओं ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रोजगार मेलों को केवल औपचारिक आयोजन न बनाकर उन्हें उद्योगों की वास्तविक मांग और युवाओं की क्षमता से जोड़ा जाए।

महंगाई और नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदेशभर में होगा विरोध-प्रदर्शन

जयपुर (हिंस)। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, बिजली और पेयजल की बढ़ती कीमतों व आपूर्ति संकट तथा नीट-2026 पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान कांग्रेस अब प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा के निर्देश पर प्रदेश की सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां 23 मई से 1 जून तक अपने-अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालयों के बाहर विरोध-प्रदर्शन करेंगी और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक और विदेश नीति के कारण देश में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई का सीधा असर आमजन के जीवन पर पड़ रहा है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, बिजली और पेयजल की आपूर्ति आवश्यकता से कम हो रही है, जिससे आमजन त्रस्त हैं। इसके अलावा नीट-2026 परीक्षा का पेपर लीक होने से लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेशभर में आयोजित होने वाले इन प्रदर्शनों के माध्यम से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

प्रदेशवासियों को बेहतर एवं उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध : मंत्री गजेंद्र सिंह

जयपुर (हिंस)। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना को लेकर मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में आरयूएचएस को रिम्स के रूप में अत्याधुनिक एवं विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थापित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर एवं उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रिम्स की स्थापना चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान एवं सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, डिजिटल हेल्थ सिस्टम तथा विशेषज्ञ सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्थान को अत्याधुनिक एवं तकनीकी रूप से सक्षम चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने आरयूएचएस अस्पताल में मानव संसाधन शीघ्र बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक कमेटी गठित की जाएगी। बैठक में रिम्स की स्थापना से जुड़े प्रशासनिक, तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने संस्थान को विश्व स्तर के चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। विशेषज्ञों ने इस संस्थान में हाई क्वालिटी क्लिनिक केयर, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शोध व अनुसंधान और इसके प्रशासनिक एवं आधारभूत ढांचे को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने रिम्स के विकास को लेकर अब तक किए गए प्रयासों एवं भावी योजना के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार इस संस्थान को विकसित करने के लिए एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार कर कार्य किया जा रहा है, ताकि टाइमलाइन में इसका कार्य पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि आरयूएचएस अस्पताल में विगत समय में कई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की गई हैं। एडवांस डायग्नोसिस प्रारंभ हो रहे हैं। इससे यहां रोगियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल रहा है। निरंतर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किए जाने से यहां ओपीडी एवं आईपीडी दोनों में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

लंबे समय से गैरहाजिर नौ महिला सहायक अध्यापक बर्खास्त

प्रयागराज (हिंस)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में परिषदीय विद्यालयों से लंबे समय से गैरहाजिर चल रही नौ महिला सहायक अध्यापकों पर शनिवार को गाज गिरी है। बीएसए अनिल कुमार ने गैरहाजिर चल रही इन शिक्षिकाओं को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का मौका देने के बाद सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है। बीएसए की इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। सेवा से बर्खास्त होने वाली शिक्षिकाएं विद्यालयों से बिना कारण बताए और छुट्टी स्वीकृत कराए गायब चल रही थीं। शिक्षिकाओं के स्कूल न आने से बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा था। वहीं सेवा नियमावली की भी अवहेलना की जा रही थी। बीएसए अनिल कुमार ने सहायक अध्यापक वंदना वर्मा, जया भार्गव, किरन त्रिपाठी, हेना परवीन, रीता देवी, ज्योति यादव, आकांक्षा रस्तोगी, अंकिता साहू और असमत जहां की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। यह सभी नौ शिक्षिकाएं बगैर किसी सूचना के लंबे समय से स्कूल से अनुपस्थित चल रही थीं।

तेजस्वी यादव ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा

पटना (हिंस)। बिहार सहित पूरे देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतें आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही हैं और सरकार इस पर गंभीर नहीं है। शनिवार को पटना में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले 10 दिनों में तेल की कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जो औसतन लगभग 50 पैसे प्रतिदिन के बराबर है। उनके अनुसार यह वृद्धि रुकने के बजाय आगे भी जारी रह सकती है, जिससे जनता पर महंगाई का दबाव और बढ़ेगा। तेजस्वी

यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की नीतियां जनविरोधी और पूंजीपरस्त सोच से प्रेरित हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं, तब भी उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं मिला। वहीं अब जब कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है, तब भी इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर डाला जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में कच्चे तेल की कीमतें कई बार कम होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। राजद नेता ने आगे कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, जिससे खाद्य वस्तुओं से लेकर परिवहन तक सभी क्षेत्रों में लागत बढ़ेगी। इसके चलते निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर घट सकते हैं, छोटे उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है और प्रवासी श्रमिकों के पलायन की स्थिति दोबारा उत्पन्न हो सकती है। इससे गरीबी और बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अन्य राजनीतिक और वैचारिक विषयों पर अधिक सक्रिय दिखती है। उनके अनुसार, जनता की मूल समस्याओं जैसे महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान संवैधानिक संस्थाओं के उपयोग, प्रचार-प्रसार और सामाजिक विभाजन से जुड़े मुद्दों की ओर अधिक रहता है, जबकि आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की नीतियों का खामियाजा अंतत: आम जनता को भुगतना पड़ता है।

गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की मांग पर अध्यापक संघ ने किया प्रदर्शन

फतेहाबाद (हिंस)। गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की मांग को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने जिला प्रधान राजपाल मिताथल की अध्यक्षता में शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संघ ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव देसराज माचरा द्वारा किया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला प्रधान राजपाल मिताथल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 16 जून 2014 और 18 जून 2014 को विभिन्न विभागों में 3 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीतियां बनाई थीं। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इन पॉलिसियों को वैध बताते हुए कच्चे कर्मचारियों और शिक्षकों को नियमित करने के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 29 अप्रैल को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स, जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी को नियमित करने का आदेश पारित किया। हाईकोर्ट के आदेशानुसार सभी अतिथि अध्यापकों को स्वयं अपना आवेदन निदेशक प्राथमिक व सेकेंडरी शिक्षा को चार सप्ताह के भीतर भेजना है, जिसकी अंतिम तिथि 27 मई

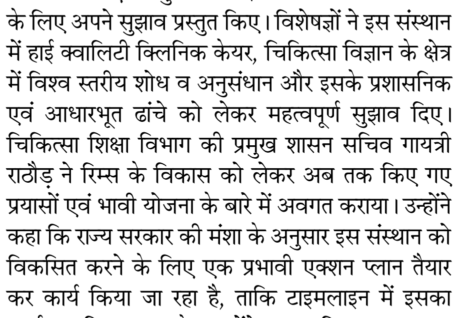

है। इसके बाद शिक्षा विभाग को 6 महीने के भीतर नियमितीकरण की यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ऐसा न करने पर विभाग को 50 हजार जुर्माना भरना पड़ेगा। राजपाल मिताथल ने रोष जताते हुए कहा कि प्रदेश और जिले के हजारों गेस्ट टीचर्स अपने-अपने स्कूल मुखियाओं के माध्यम से आवेदन दे रहे हैं, लेकिन संगठन के संज्ञान में आया है कि कई स्कूलों के मुखिया इन आवेदनों को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। संघ ने चेतावनी दी कि यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना है। संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि फतेहाबाद जिले के सभी अतिथि अध्यापकों के आवेदन बिना किसी बाधा के स्वीकार किए जाएं और समय सीमा के भीतर ही उन्हें आगामी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा जाए।

रोजगार मेला : विकसित भारत निर्माण के सारथी बनें युवा : शेखावत

जोधपुर (हिंस)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज का भारत केवल बदल नहीं रहा, बल्कि तेज गति से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन के सबसे बड़े सहभागी देश के युवा हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले केवल नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों, संघर्षों और वर्षों की तपस्या के साकार होने का उत्सव हैं। जोधपुर में आयोजित 19वें रोजगार मेले में शेखावत ने कहा कि देशभर के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित कार्यक्रमों में लगभग 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि उन लाखों परिवारों की आकांक्षाओं की जीत है जिन्होंने अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कठिन संघर्ष किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सामान्य परिवारों से आने वाले युवाओं के माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं के योग्य बनाने के लिए अनेक त्याग करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अभिभावक के लिए अपने बेटे-बेटी को पढ़ाना केवल

जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि युवाओं की सफलता के पीछे उनकी माताओं की अनगिनत प्रार्थनाएं और परिवारों का संघर्ष छिपा होता है। कितनी माताओं ने वर्षों तक दीपक जलाकर भगवान से अपने बच्चों की सफलता की प्रार्थना की होगी। कितने परिवारों ने अपनी इच्छाओं का त्याग किया होगा, तब जाकर यह दिन आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार सृजन को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से देशभर में 12 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब सरकारी भर्तियों में वर्षों लग जाते थे और प्रक्रियाओं पर सवाल उठते थे, लेकिन अब पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को समय पर अवसर मिल रहे हैं। शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। युवाओं से शेखावत ने कहा कि आज नियुक्ति पाने वाली पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है, क्योंकि उसे उस कालखंड में काम करने का अवसर मिल रहा है जब भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज 25-27 वर्ष की आयु में सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले युवा अगले दो दशकों तक भारत के परिवर्तन के प्रत्यक्ष साक्षी होंगे। आने वाले समय में आप गर्व से कह सकेंगे कि आपने विकसित भारत के निर्माण में योगदान दिया। शेखावत ने कहा कि सरकारी सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का अवसर है। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी निर्णय लेते समय सबसे गरीब व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने हर निर्णय और कार्य को समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की भावना के साथ करें।

एलआईसी की रणनीति का दिख रहा असर नान-पार पालिसियों ने बढ़ाया वीएनबी

जबूत चौथी तिमाही के प्रदर्शन के बाद बीमा कंपनी के शेयर में उछाल

नई दिल्ली

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपनी पालिसी रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है, जिसके तहत कंपनी अब ज्यादा सम-एश्योर्ड और नान-पार्टिसिपेटिंग (नान-पार) पालिसियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस रणनीतिक बदलाव का सकारात्मक असर मार्च तिमाही के वित्तीय परिणामों में साफ दिखाई दिया है, जहाँ कंपनी के नए बिजनेस के मूल्य (वीएनबी) मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। इस शानदार प्रदर्शन के बाद, प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों ने एलआईसी के लिए अपने कमाई के अनुमान और कीमत लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ा है और कंपनी के शेयर में भी तेजी देखी गई। एलआईसी के रणनीतिक बदलाव ने मार्च तिमाही में उसके वित्तीय स्वास्थ्य को काफी मजबूती दी है। एमके ग्लोबल के अनुसार, चौथी तिमाही में एलआईसी का वीएनबी मार्जिन 25.7 प्रतिशत रहा, जो उनके 20.5 प्रतिशत के अनुमान से काफी अधिक था। इस मजबूत प्रदर्शन के बाद, ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2027 और 2028 के लिए वीएनबी मार्जिन अनुमानों को 200-240 आधार अंक तक बढ़ाया है, जिससे इन वर्षों के लिए वीएनबी अनुमानों में 15-16 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। जेएम फाईनेंशियल ने वित्त वर्ष 2026 में मार्जिन में 360 आधार अंक की बढ़ोतरी का मुख्य श्रेय अनुकूल पालिसी मिश्रण को दिया है। प्रबंधन ने इस बात पर जोर दिया कि नान-पार सेगमेंट एलआईसी का सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय बना हुआ है, जिसने वित्त वर्ष 2026 में कुल वीएनबी में 53 प्रतिशत का योगदान दिया। जेएम फाइनेंशियल का अनुमान है कि व्यक्तिगत नान-पार बिजनेस के लिए मार्जिन 49 प्रतिशत, पार बिजनेस के लिए 12 प्रतिशत और ग्रुप बिजनेस के लिए 11 प्रतिशत रहेगा, जो कंपनी के व्यावसायिक मिश्रण की लाभदायकता को दर्शाता है। हालांकि, इक्विटी बाजारों में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट के कारण चौथी तिमाही में एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू (ईवी) में 6.2 प्रतिशत की कमी आई, जो 7.89 लाख करोड़ रुपये रही। यह सालाना आधार पर सिर्फ 1.6 प्रतिशत ज्यादा थी।

न्यूज़ ब्रीफ

आरबीआई ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकार्ड अधिशेष हस्तांतरित किया

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का रिकार्ड अधिशेष हस्तांतरित करने का फैसला किया है। यह राशि पिछले साल के 2.69 लाख करोड़ रुपए के लाभांश से लगभग 7 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय बैंक ने हालांकि आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) को बैलेंस शीट के 7.5 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया है, पर उच्च जोखिम प्रावधानों के कारण अर्थशास्त्रियों ने इस हस्तांतरण को बाजार की उम्मीदों से थोड़ा कम बताया है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने अपनी 623वीं बैठक में यह निर्णय लिया। इस रिकार्ड हस्तांतरण का एक प्रमुख कारण विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री से आरबीआई की आय में वृद्धि है। वित्त वर्ष 2026 में आरबीआई की बैलेंस शीट 20.61 प्रतिशत बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई, जिससे सकल आय में 26.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए सीआरबी में 1.09 लाख करोड़ रुपए का बड़ा हस्तांतरण करने का भी निर्णय लिया, जो पिछले वित्त वर्ष के 44,861.70 करोड़ रुपए से काफी अधिक है। संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा (ईसीएफ) सीआरबी को बैलेंस शीट के 4.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के बीच बनाए रखने का लचीलापन प्रदान करता है। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि सीआरबी अनुपात में कमी के बावजूद, उच्च प्रावधान आवश्यकताओं के कारण अधिशेष बाजार की उम्मीदों से थोड़ा कम रहा।

डिजिटल पीढ़ी के हाथों बदल रहा दवा बाजार, वेलनेस और लाइफस्टाइल थेरेपी में क्रांति

नई दिल्ली। भारतीय औषधि बाजार एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है, जिसकी अगुवाई देश की इंटरनेट-कुशल और स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय जेन-जी पीढ़ी कर रही है। यह युवा वर्ग अब वेलनेस, रूप-रंग और जीवनशैली से जुड़ी थेरेपी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहा है, जिससे फार्मा उद्योग पारंपरिक प्रिस्क्रिप्शन-आधारित माडल से हटकर मांग-आधारित दृष्टिकोण अपना रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि 15 से 30 वर्ष की आयु वाली यह पीढ़ी, जो देश की कुल आबादी का करीब 26 प्रतिशत है, अपनी अनूठी जीवनशैली और डिजिटल जुड़ाव के कारण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे रही है। उद्योग जगत के विश्लेषण बताते हैं कि यह समूह मोटापा-रोधी, नेत्र चिकित्सा, त्वचा संबंधी चिकित्सा और मौखिक देखभाल की दवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहा है। फार्मरैक की एक वाणिज्यिक उपाध्यक्ष के अनुसार अधिक स्क्रीन समय के कारण जेन-जी नेत्र-चिकित्सा पर काफी खर्च कर रहे हैं, जबकि त्वरित रूप-रंग सुधार की प्रवृत्ति ने इस समूह के कई लोगों को पतला दिखने के लिए मोटापा-रोधी दवाओं की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने बताया कि उच्च प्रदूषण स्तर और इंस्टाग्राम द्वारा प्रचारित सौंदर्य संस्कृति ने इस पीढ़ी को त्वचा-चिकित्सा और श्वसन संबंधी दवाओं की खपत में 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी दिलाई है।

महिंद्रा स्कार्पियो एन फेसलिफ्ट में मिलेंगे सुरक्षा फीचर्स

नई दिल्ली। जल्द ही भारतीय बाजार में महिंद्रा अपनी लोकप्रिय एसयूवी स्कार्पियो एन के फेसलिफ्ट संस्करण को पेश कर सकती है। महिंद्रा इस एसयूवी में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है, जिसमें डिजाइन के साथ-साथ आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार, नई स्कार्पियो एन के बाहरी डिजाइन में हल्के बदलाव किए जा सकते हैं। इसके साथ ही, इंटीरियर को भी अधिक प्रीमियम और आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव मिल सके। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नई स्कार्पियो एन में 10.25 इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया सेंटर कंसोल और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है, जो तकनीकी रूप से इसे और उन्नत बनाएगा। इसके अलावा, एसयूवी में पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं भी मिलने की संभावना है।

दिल्ली में पेट्रोल 100 के करीब, आठ दिनों में तीसरी बार बढ़े ईंधन के दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की तेजी से कंपनियां दाम बढ़ाने को मजबूर

नई दिल्ली

आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ एक बार फिर बढ़ गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी, जो पिछले आठ दिनों में तीसरा इजाफा है। इस नई बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 99.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल अब 100 रुपये के मनोवैज्ञानिक आंकड़े से चंद पैसे दूर है, जिससे उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही पिछले आठ दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में यह तीसरा इजाफा है। 15 मई को करीब चार साल बाद कीमतों में बदलाव करते हुए 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को 90 पैसे और अब शनिवार को यह तीसरी वृद्धि हुई है। पिछले आठ दिनों में 15 मई को शुरू हुई मूल्य वृद्धि के बाद से दिल्ली में पेट्रोल 4.77 रुपये और डीजल 4.81 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इन लगातार वृद्धियों के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट के संभावित बंद होने के खतरे ने वैश्विक कच्चे तेल के दाम 50 फीसदी से अधिक बढ़ा दिए हैं। पिछले साल औसतन 70 डालर प्रति बैरल रहने वाली भारतीय क्रूड बास्केट अब अप्रैल में 114 डालर और मई में 108 डालर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही है। सरकार और तेल कंपनियों ने जनता को एकमुश्त बड़े झटके से बचाने के लिए किश्तों में दाम बढ़ाने की रणनीति अपनाई है।

हालांकि, इन बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को आंशिक राहत मिली है, जहां उनका दैनिक घाटा 1000 करोड़ रुपये से घटकर 750 करोड़ रुपये प्रतिदिन पर आ गया है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि खुदरा कीमतों और बाजार की वास्तविक कीमतों में अब भी बड़ा अंतर है। ईंधन की इस बढ़ोतरी का सीधा असर खुदरा महंगाई दर पर पड़ेगा। आर्थिक जानकारों के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3 से 5 फीसदी की वृद्धि से मुख्य महंगाई दर में 15 से 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा हो सकता है। इससे माल ढुलाई महंगी होगी और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे सब्जी और राशन भी महंगे हो जाएंगे। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है, ऐसे में आने वाले दिनों में भी छोटे-छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

जेएसडब्ल्यू चेरी आईकार वी23 एसयूवी जल्द होगी लांच

नई दिल्ली। बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपनी नई एसयूवी को लान्च करने की तैयारी में जुट गई है। कंपनी जल्द ही जेएसडब्ल्यू चेरी आईकार वी23 को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है। लान्च से पहले इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की टेस्टिंग लगातार जारी है और हाल ही में इसे एक बार फिर परीक्षण के दौरान देखा गया है। हालांकि वाहन को पूरी तरह से ढंका गया था, लेकिन इसके डिजाइन और संभावित फीचर्स को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नई एसयूवी को बाक्सी और मजबूत डिजाइन के साथ तैयार किया जा रहा है। इसका लुक काफी हद तक मर्सिडीज जी क्लास और टोयोटा एफजे क्रूजर जैसी प्रीमियम आफ-रोड एसयूवी से प्रेरित बताया जा रहा है। वाहन में बड़ी खिड़कियां दी जा सकती हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान बेहतर विजिबिलिटी मिलने की संभावना है। इसके अलावा साइड फुटबोर्ड, पीछे टेलगेट पर जैरी कैन और बंपर के पास टेल लाइट्स जैसी सुविधाएं भी देखने को मिल सकती हैं।

डिजिटल युग में भी नकदी का अभूतपूर्व उछाल, परिचालन में रिकार्ड 42.86 लाख करोड़

नई दिल्ली

चुनावी खर्च, ग्रामीण मजबूती और महंगाई ने बढ़ाई नकदी की मांग; अर्थव्यवस्था में नकद का जारी है बोलबाला

भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रचलन के बावजूद नकदी के परिचालन में अभूतपूर्व तेजी दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 15 मई तक देश में मुद्रा का परिचालन सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़कर 42.86 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा न केवल नकदी की निरंतर मांग को रेखांकित करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में इसके अंतर्निहित कारणों पर भी बहस छेड़ता है, जो डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के बावजूद नकदी आधारित लेन-देन की मजबूती को दर्शाता है। यह जबरदस्त उछाल बताता है कि वित्त वर्ष 2026-27 के पहले डेढ़ महीनों में ही मुद्रा के परिचालन में 1.15 लाख करोड़ रुपये की भारी वृद्धि हुई है। पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक (31 मार्च, 2026) यह आंकड़ा 11.9 प्रतिशत बढ़कर 41.47 लाख करोड़ रुपये था, जबकि एक साल पहले यह 32.24 लाख करोड़ रुपये था। यह स्थिति तब सामने आई है जब भारत डिजिटल लेन-देन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक बन गया है, जो नकदी के प्रति लोगों के स्थायी झुकाव को दर्शाता है। अर्थशास्त्रियों ने इस बढ़ती नकदी मांग के पीछे कई प्रमुख कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। इनमें चुनावी गतिविधियों से जुड़ा भारी खर्च, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई मजबूती और वित्तीय संपत्तियों में अस्थिरता के बीच नकदी को एक एहतियाती उपाय के रूप में रखने की बढ़ती प्रवृत्ति शामिल है। बैंक आफ बड़ौदा के एक अर्थशास्त्री ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में परिचालन में मुद्रा में वृद्धि कई कारकों से प्रेरित प्रतीत होती है। नकदी अभी भी बड़ी संख्या में लेन-देन के लिए पसंदीदा माध्यम बनी हुई है, जबकि चुनाव-संबंधी खर्च भी आम तौर पर मतदान अवधि से पहले मुद्रा की मांग में वृद्धि का कारण बनता है।

टीवीएस का आईक्यूब स्कूटर तेजी से हो रहा लोकप्रिय

नई दिल्ली। भारत में बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक स्कूटर एक किफायती विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। कम खर्च, आसान रखरखाव और बेहतर तकनीक के कारण अब बड़ी संख्या में उपभोक्ता पेट्रोल स्कूटर छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं। भारतीय बाजार में कई ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध हैं जो एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने में सक्षम हैं। टीवीएस का आईक्यूब स्कूटर इस समय ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जिसमें 2.2 किलोवाट बैटरी दी गई है जो लगभग 94 किलोमीटर की रेंज देती है। इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। एथर कंपनी का रिज्टा माडल परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसकी चौड़ी सीट और बेहतर स्टोरेज क्षमता इसे खास बनाती है। यह स्कूटर एक बार चार्ज होने पर लगभग 123 किलोमीटर तक चल सकता है। वहीं, बजाज चेतक अपने क्लासिक डिजाइन और मजबूत धातु बाडी के कारण ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है, जिसकी रेंज करीब 113 किलोमीटर बताई गई है। ओला एस1 एयर अपनी लंबी दूरी और आधुनिक फीचर्स के कारण युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

कच्चे कपास पर 11 फीसदी आयात शुल्क हटाएगी सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी राहत

नई दिल्ली

कच्चे कपास की सभी किस्मों पर लागू 11 प्रतिशत आयात शुल्क को अस्थायी रूप से हटाने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक चार महीने की अवधि के लिए यह शुल्क हटाने पर विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को तत्काल राहत प्रदान करना है। हालांकि, इस कदम के संभावित प्रभावों को लेकर सरकारी मंत्रालयों और हितधारकों के बीच मंथन जारी है, जहाँ टेक्सटाइल क्षेत्र राहत की उम्मीद कर रहा है, वहीं किसानों के हितों की रक्षा को लेकर चिंताएं भी उठाई जा रही हैं।

वस्त्र उद्योग लंबे समय से इस शुल्क को हटाने की वकालत कर रहा है। उनका कहना है कि घरेलू कपास की कम पैदावार और पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ी कीमतों के मद्देनजर यह कदम क्षेत्र को तत्काल राहत देगा और वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय जैसे नेताओं ने भी नौकरियों के नुकसान और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री से इसे रद्द करने का आग्रह किया है।

उद्योग का मानना है कि मौजूदा शुल्क उत्पादन लागत बढ़ाता है और सिंथेटिक फाइबर की ओर अनावश्यक झुकाव पैदा करता है, क्योंकि उस पर शुल्क छूट मिलती है। वहीं सरकार के कुछ अधिकारियों और कपास व्यापार से जुड़े वर्गों का तर्क है कि सीमित समय के लिए शुल्क हटाने से किसानों पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उनका यह भी कहना है कि निर्यातक एडवांस लाइसेंस स्कीम के तहत शून्य शुल्क पर आयात कर सकते हैं, इसलिए निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बाधित होने का तर्क निराधार है। इन वर्गों को पिछली बार शुल्क हटाने के अनुभव से डालर के बहिर्वाह (1.1-1.2 अरब डालर) और खरीफ बुवाई से ठीक पहले किसानों के हितों को नुकसान पहुंचने का डर है, खासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने बेहतर कीमतों की उम्मीद में लगभग 40 लाख गांठें रोक रखी हैं। वर्तमान में, यह 11 फीसदी शुल्क 1 जनवरी 2026 से लागू है, जबकि लंबे रेशे वाले कपास पर अभी भी शून्य शुल्क है।

सुजलान एनर्जी को मिला एक और बड़ा आर्डर, राकेट बनेगा कंपनी का शेयर

मुंबई

विंड एनर्जी बनाने वाली भारत की प्रमुख कंपनी सुजलान एनर्जी को सनश्योर एनर्जी से 195 मेगावाट का एक नया और महत्वपूर्ण आर्डर मिला है। यह एक रिपीट आर्डर है, जो सुजलान के पिछले काम से सनश्योर एनर्जी की संतुष्टि को दिखाता है। इस नए आर्डर के साथ, सुजलान के खास 3 मेगावाट प्लेटफार्म वाले विंड टर्बाइनों की कुल बिक्री अब करीब 9 गीगावाट (गीगावाट) तक पहुंच गई है, जो कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

यह प्रोजेक्ट कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थापित होगा, जहां सुज़लान हवा से बिजली बनाने वाले 65 अत्याधुनिक टर्बाइन लगाएगी, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 3 मेगावाट है। कंपनी इन मशीनों की आपूर्ति के साथ-साथ उनके इंस्टालेशन, कमीशनिंग और उसके बाद के आपरेशन व मेंटेनेंस (ओक्यूएम) का पूरा जिम्मा भी संभालेगी। इस आर्डर के जुड़ने से अब कर्नाटक में सुज़लान के पास कुल मिलाकर 2 गीगावाट से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का काम आ चुका है, जो इस दक्षिणी राज्य में उसकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है।

इस डील से सुजलान और सनश्योर एनर्जी के बीच की साझेदारी अब लगभग 300 मेगावाट तक पहुंच गई है, दोनों कंपनियां महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में सक्रिय हैं। सनश्योर एनर्जी के सीईओ शशांक शर्मा ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों पर जोर देकर कहा कि क्लीन एनर्जी का अगला दौर वह होगा, जो भारत को सबसे ज्यादा जरूरत के समय बिजली दे सके। सुज़लान ग्रुप के सीईओ अजय कपूर ने भी इस डील पर खुशी जताकर कंपनी की बेहतरीन क्वालिटी, समय पर काम पूरा करने की ताकत और मशीनों की पूरी उम्र तक उनका ख्याल रखने के सपोर्ट को उनकी सफलता का आधार बताया।

हालांकि, शेयर बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि इस आर्डर से सुज़लान के शेयर प्राइस पर अल्पकालिक रूप से बहुत बड़ा या तूफानी असर देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि शार्ट टर्म में शेयर की कीमत में 1 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक का मामूली उछाल आ सकता है, क्योंकि सुजलान के पास पहले से ही 6 गीगावाट से ज्यादा के बड़े आर्डर्स लंबित हैं और बाजार इसतरह के बड़े आर्डर्स की खबर को पहले से ही भांप लेता है। फिर भी, मध्यम अवधि में यह खबर कंपनी की साख को और मजबूत करेगी और वर्तमान में 52-53 रुपये के आसपास चल रहे शेयर को सहारा देगी, जो अपने ऊपरी स्तर 74 रुपये से गिरा है।

गुजरात की सफलता में मोहम्मद सिराज व कगिसो रबाडा की अहम भूमिका रही : बांगड़

अहमदाबाद

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ ने कहा है कि आईपीएल के इस 19 वें सत्र में गुजरात टाइटंस की सफलता में तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा की अहम भूमिका रही है।

ये दोनों गेंदबाज इस सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में शामिल हैं। बांगड़ ने कहा कि इस तेज गेंदबाजी जोड़ी ने टीम की इस सत्र में सफलता की नींव रखी है। उन्होंने बताया कि इनकी अच्छी शुरुआती सफलताओं के कारण ही राशिद खान जैसे स्पिनर को बीच के ओवरों में अधिक आजादी के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिला। बांगड़ ने कहा, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा ने इस सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए बहुत ही शानदार माहौल तैयार किया है। शुरुआत में लंबे स्पेल डालने से उन्हें लगातार फील्ड या छोर बदलने की जरूरत के बिना लगातार आक्रमण करने का मौका मिला है। शुरुआती विकेट लेने की उनकी काबिलियत ने बाकी गेंदबाजी ईकाई के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार किया है। और जब टीम मैच की शुरुआत में ही बढ़त बना लेती है, तो राशिद जैसे गेंदबाज का सामना करना और भी मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर यह एक बेहतरीन तरीके से संभाला गया बॉलिंग अटैक रहा है।

बांगड़ ने इसके अलावा बल्लेबाज जोस बटलर की प्रशंसा करते हुए कहा उन्होंने इस सीजन में खूब रन बनाए हैं और अपनी बल्लेबाजी में एक अलग ही स्तर का दबदबा और आक्रामकता दिखाई है। चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ मैच को ही लें उनके स्ट्राइक रेट ने पारी का रुख पूरी तरह से बदल दिया और गुजरता को एक ऐसा स्कोर बनाने में मदद की जिसे हासिल करना सीएसके के लिए असंभव हो गया। साथ ही कहा कि अब इन खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन का लाभ टीम को प्लेऑफ में मिलेगा।

न्यूज ब्रीफ

टी20 महिला विश्व कप में जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम : मंधाना

बेंगलुरु। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अगले माह होने वाले टी20 विश्वकप की तैयारियां में लगी है। भारतीय टीम का लक्ष्य एकदिवसीय के बाद टी20 खिताब भी अपने नाम करना है और टीम इसको लेकर प्रयास भी कर रही है। टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने का कहना है कि टीम टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और वह जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं रखेगी। यह टूर्नामेंट 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। इसमें भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को परंपरागत प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से करेगी। मंधाना टीम की तैयारियों से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, हमारा अभ्यास शिविर बहुत अच्छा रहा। मैं अभी इस बारे में इतना ही बताना चाहती हूं। साथ ही कहा कि सभी खिलाड़ी अच्छी स्थिति में दिख रही हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया है और सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। टीम में एक सकारात्मक ऊर्जा है और हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक है। भारतीय टीम ने बेंगलुरु के सेंटर आफ एक्सीलेंस (सीओई) में एक गहन अभ्यास शिविर में हिस्सा लिया। इस शिविर का उद्देश्य खिलाड़ियों को आगामी चुनौतियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना था, जिसमें फिटनेस, फील्डिंग और विभिन्न मैच परिदृश्यों पर काम किया गया। टीम 22 मई को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की महत्वपूर्ण टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलने के लिए रवाना होगी। इससे टीम को टूर्नामेंट के लिए लय हासिल करने में सहायता मिलेगी मंधाना ने जोर देकर कहा कि टीम अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त है और उसका एकमात्र लक्ष्य विश्व कप जीतना है।

सचिन से तुलना कर अनावश्यक वैभव पर दबाव न बनायें : दिनेश कार्तिक

मुम्बई। 15 के वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इस सत्र में राजस्थान रायल्स की ओर से खेलते हुए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि वैभव भविष्य में दूसरे सचिन तेदुलकर बनेंगे जिसे पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक सही नहीं मानने। कार्तिक का कहना है कि इस प्रकार से किसी भी उभरते हुए खिलाड़ी पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिये। कार्तिक ने जोर देकर कहा है कि वैभव को अपने रास्ते पर चलने देना चाहिए और उन पर अनावश्यक तुलना का बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे उनके करियर में बाधाएं आ सकती हैं। गौरतलब है कि पिछले साल आईपीएल में पदार्पण के बाद से ही वैभव की चर्चा हर तरफ है। इस क्रिकेटर ने केवल 15 साल की उम्र में विश्व के दिग्गज गेंदबाजों पर भी बड़े शाट लगाकर दिखा दिया कि वह किसी मामले में पीछे नहीं है। आईपीएल के मौजूदा सीजन में वह लगातार आरेंज कैप की दौड़ में बने हुए है और सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। बाएं हाथ के इस ओपनर ने 13 मैचों में 579 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 236.32 का रहा है, जिससे वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर हैं। वहीं कार्तिक अभी रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजी कोच और मेंटर हैं, ने इस तुलना पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, जो वैभव कर रहा है, वह बहुत खास है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग उसे अगला सचिन कहें क्योंकि वह सिर्फ 15 साल का है। उसे वही करने दो जो वह कर रहा है। मुझे लगता है कि सचिन ने जो किया वह असाधारण था और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कार्तिक ने यह भी स्पष्ट किया कि वैभव को अपने करियर में सचिन से बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, सचिन की चुनौतियां मैदान के अंदर जितनी थीं, उतनी ही मैदान के बाहर भी थीं।

वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल बोले, आईपीएल में बिहार की भी टीम हो

मुम्बई। देश के बड़े उद्योगपति और वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल ने कहा है कि बिहार में इतनी प्रतिभाएं है कि आईपीएल में उसकी एक टीम तक बन जाये। इससे अब आईपीएल में बिहार से भी एक टीम लाने की मांग उठने लगी है। अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि बिहार में क्रिकेट की आपार प्रतिभाएं है बस उन्हें पहचान के लिए एक मंच मिलना चाहिये। उनके इस बयान के बाद राज्य भर के क्रिकेट प्रेमियों और खेल जगत में उत्साह और चर्चा का माहौल है कि क्या आने वाले समय में बिहार की अपनी एक आईपीएल टीम देखने को मिलेगी। मूल रूप से बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल का अपने गृह राज्य से गहरा जुड़ाव हमेशा बना रहता है। वे अक्सर ही बिहार की तारीफ करते हैं और यहां के युवाओं की प्रतिभा का जिक्र करते रहते हैं। उनका यह नया बयान इसी जुड़ाव और राज्य के प्रति उनकी भावनाओं को दिखाता है। अपने पोस्ट में अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसी तरह बिहार की भी एक मजबूत और प्रतिष्ठित आईपीएल टीम होनी चाहिए।

आईपीएल 2026 : आरेंज कैप रेस में क्लासेन तीसरे स्थान पर, ईशान किशन टाप-5 में पहुंचे

नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लीग चरण के अंतिम दौर में आरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस बेहद रोमांचक हो गई है। शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद और रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबले के बाद दोनों सूचियों में कई अहम बदलाव देखने को मिले।

आरेंज कैप की दौड़ में क्लासेन की बड़ी छलांग

गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन 638 रनों के साथ अब भी आरेंज कैप की रेस में शीर्ष पर बने हुए हैं। उनके साथी और कप्तान शुभमन गिल 616 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने आरसीबी के खिलाफ सिर्फ 24 गेंदों में 51 रनों की तेज पारी खेलकर तीसरे स्थान पर छलांग लगा दी है। क्लासेन के अब 14 पारियों में 606 रन हो गए हैं।

राजस्थान रायल्स के वैभव सूर्यवंशी 579 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं। वहीं, एसआरएच के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने आरसीबी के खिलाफ 46 गेंदों में 79 रन बनाकर टाप-5 में जगह बना ली है। किशन के अब 569 रन हो गए हैं।

पर्पल कैप में भुवनेश्वर और रबाडा बराबरी पर

पर्पल कैप की दौड़ में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा संयुक्त रूप से 24-24 विकेट लेकर शीर्ष पर बने हुए हैं। हालांकि, बेहतर इकानमी रेट (8.07) होने के कारण पर्पल कैप फिलहाल भुवनेश्वर कुमार के पास ही बनी हुई है, जबकि रबाडा की इकानमी 9.18 है। चेन्नई सुपर किंग्स के युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज 21 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। गुजरात टाइटंस के स्टार स्पिनर राशिद खान 19 विकेट लेकर चौथे नंबर पर मौजूद हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा ने आरसीबी के खिलाफ 2 विकेट लेकर अपने विकेटों की संख्या 19 तक पहुंचा दी, लेकिन उनकी इकानमी 9.27 होने के कारण वह पांचवें स्थान पर हैं।

आस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए प्रतिबद्ध हूं : कमिंस

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में आजकल सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पैट कमिंस ने कहा है कि अगले कुछ साल तक उनकी पहली प्राथमिकता आस्ट्रेलियाई टीम से खेलना ही रहेगा। कमिंस का ये बयान तब आया है जब खेल जगत में इस बात की बहस चल रही है कि आस्ट्रेलिया के कुछ शीर्ष खिलाड़ी आईपीएल के अलावा अन्य आकर्षक फ्रेंचाइजी लीगों के लिए राष्ट्रीय टीम की उपेक्षा कर रहे हैं। वहीं कमिंस ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि उनकी प्रतिबद्धता आस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ी हुई है हालांकि वह आईपीएल प्लेआफ को देखते हुए आगामी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरों से बाहर रहने वाले हैं। वह इसके अलावा अन्य सब मुकाबलों मे खेलेंगे। अगस्त 2026 से अगस्त 2027 के बीच होने वाले संभावित 20 से 21 टेस्ट मैचों, जिनमें भारत में प्रतिष्ठित बार्डर-गावस्कर ट्राफी और इंग्लैंड में एशेज सीरीज जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले शामिल इसमें वह शामिल रहेंगे। आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और बिग बैश लीग (बीबीएल) दोनों के प्रति प्रतिबद्धता का मुद्दा हाल के समय में छाया रहा है। कुछ समय पहले, पांच अनुभवी खिलाड़ी क्रिकेट आस्ट्रेलिया के शुरुआती अनुबंध प्रस्तावों से हटकर लीग क्रिकेट खेलने लगे थे जिससे बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच मतभेदों भी सामने आ गये। मार्च महीने में कमिंस खुद निशाने पर थे जब उन्होंने खिलाड़ियों के बीच एक तनाव होने की बात कही थी। यह तनाव अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट खेलने की राष्ट्रीय जिम्मेदारी और उसी समय इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग में खेलकर लगभग 6.75 लाख आस्ट्रेलियाई डालर (लगभग 4.85 लाख अमेरिकी डालर) कमाने के अवसर को छोड़ने के बीच की दुविधा को बताता था। वहीं अब एक कार्यकम में कमिंस ने अपनी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा कि निकट भविष्य के लिए आस्ट्रेलिया क्रिकेट के प्रति वह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने से कहा, मेरे लिए कुछ नहीं बदला है। मेरी पहली प्राथमिकता आस्ट्रेलियाई क्रिकेट है, खासकर टेस्ट क्रिकेट।

सुपर चेस क्लासिक : आर. प्रज्ञानानंद का मुकाबला ड्रा खिताब की दौड़ हुई रोमांचक

बुखारेस्ट

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने जीत के कई मौके गंवाए और फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लग्रेव के खिलाफ शुक्रवार को मुकाबला ड्रा खेला। इसके साथ ही सुपर चेस क्लासिक टूर्नामेंट में खिताब की दौड़ अंतिम दौर से पहले बेहद रोमांचक हो गई है।

नौवें और अंतिम से पहले राउंड में अमेरिका के फैबियानो कारुआना और जर्मनी के विन्सेंट कीमर के बीच मुकाबला ड्रा रहा। वहीं उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए नीदरलैंड्स के जार्डन वान फारेस्ट को हराया।

डच खिलाड़ियों के लिए यह दिन निराशाजनक रहा, क्योंकि अनिश गिरी को रोमानिया के बोगदान-डेनियल डियाक के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं अमेरिका के वेस्ले सो को फ्रांस के अलीरेज़ा फिरूजा के टूर्नामेंट से हटने के कारण वाकओवर मिला।

अब अंतिम राउंड से पहले कारुआना और कीमर पांच-पांच अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। सिंदारोव, वेस्ले सो और जार्डन वान फारेस्ट साढ़े चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। प्रज्ञानानंदा, गिरी और वाचियर-लग्रेव चार-चार अंकों के साथ संयुक्त छठे स्थान पर मौजूद हैं। प्रज्ञानानंद ने ग्रुनफेल्ड डिफेंस ओपनिंग में सफेद मोहरों से खेलते हुए सातवीं चाल पर नया प्रयोग किया, जो शीर्ष स्तर पर पहले कभी नहीं देखा गया था। शुरुआती मिडिल गेम में भारतीय खिलाड़ी मजबूत स्थिति में थे और लग रहा था कि मुकाबला जल्द उनके पक्ष में समाप्त हो जाएगा। हालांकि कुछ गलतियों के कारण मुकाबला क्वीन और प्यादों के एंडगेम तक पहुंच गया, जहां प्रज्ञानानंद के पास अतिरिक्त प्यादा था। समय के दबाव के बावजूद उन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा। टूर्नामेंट का सबसे लंबा मुकाबला आखिरकार 139 चालों के बाद ड्रा पर समाप्त हुआ। दूसरी ओर, सिंदारोव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एंडगेम में अपने नाइट और रूख की मदद से बेहतरीन मात का जाल बिछाकर जीत दर्ज की।

टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 3 लाख 75 हजार अमेरिकी डालर है, जिसमें विजेता को 1 लाख डालर मिलेंगे। यदि शीर्ष पर बराबरी रहती है, तो विजेता तय करने के लिए टाईब्रेक मुकाबले खेले जाएंगे।

एशियन जूनियर टेनिस में तारुष और इवाना को दोहरा खिताब

इंदौर। इंदौर टेनिस क्लब के प्रांगण में खेली गई प्रतिष्ठित पुनित मेमोरियल एशियन जूनियर अंडर-12 इंदौर ओपन टेनिस स्पर्धा में भारत के उदीयमान खिलाड़ी तारुष बीसी और इवाना अरोरा ने अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दोहरी सफलता अर्जित की है। मध्य प्रदेश टेनिस संघ के तत्वावधान में आयोजित तथा पाथ फाउंडेशन व मोयरा सरिया द्वारा प्रायोजित इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में दोनों ही खिलाड़ियों ने एकल (सिंगल्स) के साथ-साथ युगल (डबल्स) वर्ग में भी धमाकेदार प्रदर्शन कर डबल टाइटल अपने नाम किए। बालिका एकल वर्ग के बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में इवाना अरोरा ने अपनी दमदार सर्विस और सटीक फोरहैंड शाट्स के बूते छठी वरीयता प्राप्त पी. चटर्जी को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। पूरे मैच के दौरान इवाना का खेल इतना सधा हुआ और आक्रामक था कि चटर्जी को प्रत्येक अंक अर्जित करने के लिए अंत तक कड़ा संघर्ष करना पड़ा।

कार्तिक ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया : रैना

मुम्बई

भारतीय टीम के पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की ओर से खेल रहे गेंदबाज कार्तिक त्यागी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उसने इस सत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है। रैना ने कहा कि इस गेंदबाज को पिछली बार किसी ने भी नहीं खरीदा था ऐसे में देखा जाये तो इस बार उसकी वापसी धमाकेदार रही।

उनके मुताबिक, लीग से बाहर रहने के इस समय का इस गेंदबाज ने सही तरीके से उपयोग किया। इस दौरान उन्होंने खेल के मैदान से दूर रहकर अपने शरीर और मन दोनों पर काम किया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर गहन काम किया, पुरानी चोटों से उबरने के लिए समर्पित रहे और अपने खेल को फिर से धार दी।

रैना के अनुसार, 2025 की नीलामी में न बिकना उनके लिए एक ब्रेक का अवसर बन गया, जिसने उन्हें अपने शरीर और फार्म को पूरी तरह से बेहतर बनाने में मदद की।

इस सीजन में कार्तिक के प्रदर्शन में आया बदलाव वाकई असाधारण रहा है। उन्होंने 13 मैचों में 18 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में उनके बेहद कम मैचों में खेलने और सीमित सफलता हासिल करने के बिल्कुल उलट है। रैना ने कहा, कार्तिक निश्चित रूप से इस आईपीएल सत्र की वापसी की कहानी हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस पर बहुत मेहनत की है और उसका उन्हें सीधा फायदा मिला है।

रैना ने कहा, 2022 में उन्होंने केवल दो मैच खेले और एक विकेट लिया, 2023 में तीन मैच खेलकर एक विकेट लिया और 2024 में तो वे सिर्फ एक मैच ही खेल पाए थे। 2025 की नीलामी में किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। वहीं इस सीजन में, उनका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने 13 मैच खेले हैं और 18 विकेट लिए हैं। उन्होंने आगे उम्मीद जताई कि इस गेंदबाज के लिए आगे भी कई और सफल सीजन आएंगे। रैना का मानना है कि अगर वह अपनी फिटनेस और फार्म को बनाए रखते हैं, तो उन्हें भारत के लिए खेलने से कोई नहीं रोक सकता।

सिख प्रीमियर लीग में बब्बर शेर इलेवन और स्पार्टन्स की धमाकेदार जीत

तेजिंदर सिंह के धुआंधार नाबाद अर्धशतक से विष्णुपुरी इलेवन भी विजयी; मन्नी इलेवन और प्रताप नगर को मिली करारी शिकस्त

इंदौर

विष्णुपुरी के सचखंड मार्ग स्थित गुरु अरजन देव खेल मैदान पर आयोजित चढ़दी कला ट्राफी सिख प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा के पांचवें दिन बब्बर शेर इलेवन, स्पार्टन्स (चढ़तीकला) और विष्णुपुरी इलेवन ने विरोधी टीमों को चारों खाने चित करते हुए शानदार जीत दर्ज की। मैदान पर लग रहे गगनचुंबी छक्कों और विकेटों के पतन पर बजने वाले पारंपरिक ढोल-धमाकों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। इस खेल उत्सव का आनंद लेने के लिए सिख समाज के बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर अपनी चहेती विजेता टीमों का जमकर उत्साहवर्धन किया।

दिन के पहले मुकाबले में बब्बर शेर इलेवन ने मैदान पर उतरते ही आक्रामक रुख अपनाया। टीम ने निर्धारित 8 ओवरों में 6 विकेट खोकर 102 रनों का विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जिसमें कपिल सिंह ने बल्ले से अत्यंत उम्दा योगदान दिया। जवाब में रनों के इस भारी दबाव के आगे मन्नी इलेवन की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मन्नी इलेवन 8 ओवरों में 6 विकेट पर महज 42 रन ही बना सकी और बब्बर शेर इलेवन ने 60 रनों के बड़े अंतर से मैच अपनी झोली में डाल लिया।

तरनप्रीत के तूफान से जीता स्पार्टन्स

दूसरे मैच में स्पार्टन्स (चढ़तीकला) ने सिंह इलेवन प्रताप नगर के खिलाफ 3 विकेट से रोमांचक फतह हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए सिंह इलेवन प्रताप नगर ने 8 ओवरों में 6 विकेट खोकर 104 रनों का मजबूत स्कोर बनाया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्पार्टन्स टीम के लिए स्टार बल्लेबाज तरनप्रीत सिंह संकटमोचक बने। उन्होंने मात्र 15 गेंदों पर 46 रनों की आतिशी पारी खेलकर मैच का पासा पलट दिया। स्पार्टन्स ने दो गेंद और 3 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया।

विष्णुपुरी इलेवन की 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत

दिन के एक अन्य मुकाबले में विष्णुपुरी इलेवन ने सिख योद्धा इलेवन को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर मैदान मार लिया। इस एकतरफा जीत के महानायक तेजिंदर सिंह रहे, जिन्होंने महज 20 गेंदों में 52 रनों की नाबाद और विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेलकर विपक्षी टीम को मुकाबले से पूरी तरह बाहर कर दिया।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

रोमांचक मैचों के बीच शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खेल मैदान पर पहुंचकर खिलाड़ियों और आयोजनकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने इस सफल आयोजन की खेल भावना, अनुशासन और सामाजिक एकजुटता की मुक्तकंठ से सराहना की। इस अवसर पर अमरजीत सिंह बग्गा, प्रीतपाल सिंह भाटिया, कैलाश पिपले, वकील पठान, जसबीर सिंह गांधी, रवि तोमर, महेश बसवाल, राजेश उदावत, महेश जोशी, रवि जैन, जितेंद्र जैन और काशी सचान उपस्थित थे। अतिथियों का आत्मीय स्वागत हरपाल सिंह भाटिया, चरणजीत सिंह सैनी, हरप्रीत सिंह बक्शी, अमरजीत सिंह भाटिया और सुखजिंदर चहल ने किया।

कांगू वर्कआउट से जुड़ी बातों को जानें

क्या आप जानते है कि कांगू जम्प आपके शरीर को कई तरह के आराम पंहुचाता है। एक्सरसाइज शरीर के लिए जरूरी होती है पर कई बार बोरिंग लगती है। लेकिन कांगू जम्प के साथ आपको ऐसी शिकायत नही रहेगी। नाचते भागते करने वाली ये एक्सरसाइज आपके शरीर पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हुए आसानी से आपको स्वस्थ रखती है।

जब हो पहली फिटनेस क्लास

किसी भी नई चीज की शुरुआत के दौरान हम काफी बेचैनी महसूस करते हैं। नतीजतन हम गहरे प्रेशर में आ जाते हैं या फिर हमारा आत्मविश्वास डोल जाता है। ठीक यही बात पहली फिटनेस क्लास पर भी लागू होती है। यहां ऐसे ही बातों का जिक्र हो रहा है।

छुपकर रहना

नई फिटनेस क्लास में अकसर लोग फिटनेस इंस्ट्रक्टर से छिपने की कोशिश करते हैं। मानों उनकी परीक्षा ली जा रही हो। जबकि ऐसा करने की बजाय फिट रहने के लिए इंस्ट्रक्टर से नजदीकियां बढ़ाना आवश्यक है।

इंस्ट्रक्टर की नजर

यदि आपका इंस्ट्रक्टर आपसे कहे कि उसकी नजर आप पर है तो इस बात से परेशान न हो। असल में ज्यादातर लोग अपनी नई फिटनेस क्लास में इंस्ट्रक्टर से डरते हैं। ध्यान रखें कि वे भी कभी नवसीखिए थे। अतः खुद को सबसे पिछड़ा हुआ न समझें।

पोस्चर पर नजर

मैं कैसा दिख रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? वगैरह-वगैरह। फिटनेस सेंटर में एक्सरसाइज करते वक्त इस तरह की बातें भी अकसर परेशान करती हैं। लेकिन यकीन मानिए फिटनेस क्लास में फैशन से ज्यादा कम्फर्ट मायने रखता है।

इंस्ट्रक्टर का पागलपन

नई क्लास में इंस्ट्रक्टर अकसर समझ नहीं आते। यही कारण है कि शुरुआत में हमें इंस्ट्रक्टर का अच्छा खासा खौफ रहता है। लेकिन इस विषय में परेशान होने की बजाय जरूरी यह है कि उसे समझें। उससे नजरें न चुराएं। समस्या होने पर उससे सीधे संपर्क करें।

मशीन की जानकारी

निःसंदेह इस दुनिया में हर कोई पर्फेक्ट नहीं है। ऐसे में यदि फिटनेस क्लास में आपको कोई नई मशीन दिखती है तो उस संदर्भ में फिटनसे इंस्ट्रक्टर से पूछने में हिचकिचाएं नहीं। जबकि नई क्लास में भी लोग इस सवाल को पूछने से बचते हैं।

प्रतिस्पर्धा से बचें

किसने कौन सी मशीन में एक्सरसाइज की है या किसने कितना वजन उठाया है? इस तरह के सवाल पहली क्लास में आना लाजिमी है। लेकिन आप पहले ही दिन उनसे अपनी तुलना न करने लगे। याद रखें तुलना करेंगे तो नुकसान में रहेंगे।

अकेले वार्म अप करना

अकेले वार्म अप करने में कई लोग शर्म महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? बिल्कुल नहीं। शुरुआती स्तर में वार्म अप करना आवश्यक है। अतः दूसरों की अनदेखी करें और एक्सरसाइज पर ध्यान दें।

तालमेल न बैठना

हो सकता है कि पहली क्लास में आपका फिटनेस सेंटर में मौजूद अन्य लोगों के साथ तालमेल न बैठे। लेकिन इसको समस्या का सबब नहीं बनाना चाहिए, न ही चिंता का विषय। इसके इतर जरूरी यह है कि उन्हें देखते हुए एक्सरसाइज पर ध्यान दें।

क्या मैं सही कर रहा हूं

फिटनेस सेंटर में पहले दिन इस तरह का ख्याल भी बार बार आता है। असल में हम फिटनेस क्लास के पहले दिन खुद को कम और दूसरों को ज्यादा देखते हैं। नतीजतन बार बार खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं। याद रखें कि अगर आपकी एक्सरसाइज गलत होगी तो इंस्ट्रक्टर खुद आपकी मदद करेंगे।

नए खून में आक्रामक व्यवहार...

इस लेख में युवाओं को समझने का प्रयास किया गया है ताकि हमें मुद्दों की सही समझ हो और हम अपने व्यवहार में सही परिवर्तन ला सकें। आक्रामकता ऐसे भौतिक या मौखिक व्यवहार को कहते हैं जिसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना होता है।

आक्रामकता दो तरह की होती हैं, पहली, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, जो गुस्से से पनपती है और इसका मकसद दूसरों को घायल करना होता है। दूसरी होती है औजार के तौर इस्तेमाल होने वाली आक्रामकता। इसमें आक्रामकता को हथियार बनाकर कोई मकसद हासिल किया जाता है और इसमें हमलावर व्यक्ति को उकसाने वाला मौलिक तत्व दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं होता। मिसाल के तौर कोई लड़का अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी कक्षा के किसी लड़के को उसके किसी व्यवहार से खफा होकर उसे पीटता है क्योंकि वह उससे बदला लेना चाहता है। यह शत्रुतापूर्ण आक्रामकता है जो आवेश और भावनात्मक उफान से जन्मी है। दूसरी ओर किसी खास अच्छे या बुरे मकसद के लिए जुनून की तरह आक्रामकता सामने आती है जो सामाजिक राष्ट्रीय हितों की रक्षा या के लिए भी हो सकती है।

बच्चा आक्रामक क्यों होता है?

एक मत यह है कि मूल प्रवृत्ति और कुंठा हमारे भीतर आक्रामकता की प्रबल भावना पैदा करती है जबकि दूसरा मत यह है कि सीखने से हमारे भीतर की आक्रामकता बाहर आती है। इसका मतलब यह हुआ कि अनुभव और दूसरों को देखने से हम यह सीखते हैं कि आक्रामकता से कुछ हासिल होता है। किसी बच्चों के आक्रामक व्यवहार से दूसरे घबरा जाते हैं तो अन्य बच्चों में यह प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका उन बच्चों से अधिक होती है, जो किसी बात का कड़ा दंड भुगत चुके होते हैं।

आक्रामकता एक जीव विज्ञान है

कुछ जैविक कारण भी आक्रामकता पैदा करते हैं जिनमें हार्मोन में परिवर्तन आना और शराब पीने से जनित आक्रामकता आदि शामिल हैं।

आपराधिक व्यवहार को समझना मनोविश्लेषण

मनोविश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति में बहुत विध्वंसक प्रवृत्तियां होती हैं वह शुरुआती विकास के चरण में दबा हुआ होता है और वह अपने एवं वातावरण के बीच समायोजन नहीं कर पाता। इसका अर्थ यहां यह हुआ कि व्यक्तियों की अवधारणात्मक सोच शुरुआती स्तर पर पनपती है और यह विकसित अवस्था में नहीं बन पाती।

व्यक्तित्व के विकार

ऐसे व्यक्तियों में समाज विरोधी व्यक्तित्व के विकार भी होते हैं। इन व्यक्तियों में सामाजिक नियमों से बंधने की प्रवृत्ति नहीं होती, उनका आवेश पर नियंत्रण खराब होता है, वे बहुत आक्रामक होते हैं और उनमें पछतावे की भावना नहीं होती। ये लक्षण बहुत शुरुआत में ही पनप जाते हैं। बच्चों में इसे 'आचरण विकार' वाले व्यक्तित्व के तौर पर देखा जाता है। ऐसे बच्चे बहुत छिपाव वाले, आक्रामक और सभी नियमों को तोड़ने वाले होते हैं।

समूह मनोविज्ञान

इनमें से अनेक किशोर अपना गुट बना लेते हैं। ऐसे गुट में आपसी जुड़ाव बहुत मजबूत होता है और शुरुआती वर्षों में ही वे गुटों में शामिल हो चुके होते हैं। इस प्रक्रिया को 'निवैयक्तिकरण' कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपना आत्मबोध खो देता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती। वह ग्रुप में ही सोच पाता है और उसकी अपनी पहचान खत्म होती है। वह ग्रुप में ही अपनी पहचान देख पाता है। इसी वजह से वह जो कुछ करता है, गुट में करता है और गुट न हो तो वह कुछ नहीं कर पाता।

देखकर सीखना

जब कोई बच्चा शुरूआती जीवन में हिंसा देखता है तो उसके मन में इसके प्रति संवेदनशीलता कम होती जाती है और वह बिना किसी पश्चाताप के हिंसा में संलग्न हो सकता है। जो लड़के विध्वंस और हिंसा के सम्पर्क में अधिक रहते हैं, उन पर इसका बहुत अधिक असर पड़ता है। हिंसा में लगे रहने वाले दोस्तों के सम्पर्क में रहने वाले लड़कों या आक्रामक माता-पिता के साथ जीने वालों में आक्रामकता पैदा होती है और वे हिंसा और अपराध से हिचकिचाते नहीं हैं।

अन्य कारण

सामाजिक-आर्थिक भेद की भूमिका: जो विभिन्न सामाजिक गुटों के बीच बढ़ता भेदभाव देखता है, उससे अपेक्षाकृत वंचित होने की भावना बढ़ती है। इससे युवाओं में आपराधिक व्यवहार भी बढ़ता है।

कानूनी प्रणाली: जब बड़े अपराधिक मामलों में किसी को सजा नहीं हो पाती और मामलों में देरी होती रहती है तो इससे किशोरों के मन में यह भावना पनपती है कि वे अपराध से बच निकलेंगे और इससे उनका भय कम होता है।

टेलीविजन: टीवी में काफी हिंसा दिखाई जाती है। अध्ययनों से पता चला है कि हिंसा देखने से आक्रामक व्यवहार में बढ़ोत्तरी होती है क्योंकि इससे देखने वाले की हिचक कम होती है। आक्रामक विचारों से दर्शक की हिंसा के प्रति संवेदनशीलता पर असर पड़ता है। टीवी पर हिंसा देखने का मुख्य प्रभाव हिंसा के प्रति हिचक खोना और संवेदनशीलता घटने के तौर पर होता है और वास्तविक अवधारणा तथा सीखी गई अवधारणा में विकार आता है। लिहाजा यह जरूरी है कि बच्चों को हिंसक कार्यम न देखने दिए जाएं और अभिभावक उन पर अपना सख्त नियंत्रण रखें।

नशे का इस्तेमाल

यह देखने में आया है कि किशोरों में शराब और अन्य रसायन लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका हिंसा और आक्रामकता से सीधा संबंध है। हिंसक व्यवहार को बढ़ावा देने वाले कारक अनेक शोध अध्ययनों से निष्कर्ष निकला है कि जटिल संवादों और विभिन्न कारकों के मिलने से किशोरों और बच्चों में हिंसक व्यवहार का जोखिम पैदा होता है। इन कारकों में शामिल है -

- पिछले आक्रामक या हिंसक व्यवहार
- भौतिक या यौन प्रताड़ना का शिकार होना
- घर या समुदाय में हिंसा का सामना करना

आनुवांशिक कारण

- मीडिया, टीवी फिल्म आदि में हिंसा देखना
- शराब या नशा करना एवं घर में हथियार होना
- तनावपूर्ण पारिवारिक सामाजिक आर्थिक कारण (गरीबी, बेहद वंचित होना, शादी टूटना, तलाकशुदा मां या पिता के साथ जीना, बेरोजगारी, परिवार से समर्थन बंद होना आदि)

हिंसक व्यवहार के सिगनल क्या हैं?

जो बच्चा गंभीर हिंसक प्रवृत्ति का शिकार हो सकते हैं उनमें ये लक्षण देखे जा सकते हैं

- बेहद गुस्सैल
- अक्सर बेकाबू होना और झगड़ने पर आमादा
- बेहद चिड़चिड़ा होना
- अत्यंत आवेश में रहना
- आसानी से कुंठित होना

हिंसक व्यवहार का पैमाना

बच्चों और किशोरों में हिंसक व्यवहार जिन हदों तक जा सकता हैं वे हैं - विस्फोटक मिजाज, भौतिक आक्रामकता, लड़ाई, धमकियां और या दूसरों को चोट पहुंचाना, हथियारों का इस्तेमाल करना, जानवरों के प्रति क्रूरता, आग लगाना, सम्पत्ति को जानबूझ कर नुकसान पहुंचाना और तोड़फोड़ करना।

भरपूर ऊर्जा से जिएं जिंदगी...

छोटी-छोटी बातें आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकती हैं आप ऐसी ही बातों का खयाल रखें और सुकूनभरी जिंदगी का स्वागत करें। आप जिंदगी को भरपूर ऊर्जा के साथ जिएं। कुछ चीजें जो आपके नियंत्रण में न हों उन्हें होने दें। उसके लिए व्यर्थ ही परेशान न हों।

जैसे मौसम का प्रभाव, बस का देर से आना, लोगों का व्यवहार और ट्रैफिक की लंबी की कतार। कई लोग ऐसी परिस्थितियों में नियंत्रण खो देते हैं और तनाव में आ जाते हैं। इस तरह से जीने का आखिर मतलब क्या है? अपने जीवन में उर्जा को बनाए रखें और जीवन में आने वाले सकरात्मक बदलावों को महसूस कीजिए।

आशावादी नजरिया अपनाएं

दुनिया के बारे में एक आशावादी नजरिया अपनाए जाने की जरूरत है। अक्सर होता ये है कि हमारा पूरा फोकस समस्याओं पर ही होता है। इस तरह की सोच कभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती है।

आप आज से ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें और देखें कि बाहरी दुनिया कितनी खूबसूरत है। सोचें एक सुबह जो हर रोज नई शुरुआत का मौका देती है, एक दोपहर जो आपको आगे बढने को प्रेरित करती है। एक शाम जो दुनिया की सुंदरता से परिचित करती है। रात जब आती है तो सोचने-विचारने का मौका देती है एक नये दिन की शुरुआत के लिए आराम भी। आपके इस जीवन में सौंदर्य, प्रेम, दया, सबकुछ है. लेकिन नकारात्मक सोच के कारण आप इस ओर नहीं देख पाते हैं। एक बार सकारात्मक नजरिया अपनाकर देखें, आप पाएंगे कि अचानक कुछ अच्छा लगने लगा है। बस जीवन में आने वाली खुशियों का इंतजार करें। आपको अपनी किस्मत अच्छी लगने लगेगी।

गुस्सा करना छोड़ें

एक बार गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी पर गुस्सा करना उस पर गर्म कोयले से प्रहार करने जैसा है जिससे कि तुम भी जलोगे। इसलिए आप दूसरों पर गुस्सा करना करना छोड़ दें। इसका प्रभाव दूसरे से ज्यादा आप पर पड़ेगा। अगर आप दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं तो आप पाएंगे की कि दुनिया में बहुत से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। यह स्थिति यथार्थ से भागने की नहीं बल्कि उसके और ज्यादा करीब जाने की है। अपने जीवन को जंग मत बनाइए। आपकी ही तरह आपके करीबियों को भी आपके प्रेम, और सम्मान की जरूरत है।

जड़ता को छोड़ें

डेविड कैम्पबेल ने एक बार कहा था तुम जो करना चाहते हो, उसको बार-बार याद करना ही अनुशासन है। अपने जीवन में कुछ सपने मूल्य और नजरिया विकसित कर लेना चाहिए। दृढ इच्छा शक्ति के दम पर ही जीवन में खुशियों को पाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि आप एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं। आपको सोचने की फुर्सत ही नहीं बस दौड़े जा रहे हैं। इस जड़ता को छोड़ दीजिए। ठहरकर सोचें और फिर उद्देश्य और सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढें।

खुद फैसले लेना सीखें

कही आप अपने फैसले लेने में हिचकिचाते तो नहीं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपके फैसलों के बारे में क्या सोचता है। आप खुद को दूसरों से बेहतर जानते हैं, इसलिए ये आपको ही डिसाइड करना है कि आपको अपने जीवन और खुशियों को बनाए रखने के लिए क्या करना है। यह जान लें कि आपको समझे और जाने बिना कोई भी व्यक्ति आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति आपको पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। इसलिए आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें। आपको लगेगा आप सही मायने में जीवन जी रहे हैं। ऐसा करने पर आपको महसूस होगा कि आप खुद में संपूर्ण हैं और दुनिया में किसी से भी ज्यादा खूबसूरती से जी रहे हैं।

रेसिपी

नींबू का खट्टा- मीठा अचार

सामग्री

आधा किलो नींबू, आधा किलो शक्कर, 1 से 2 छोटी चम्मच काला नमक, एक छोटी चम्मच बड़ी इलाइची पाउडर, 6 से 8 पिसी काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, 4 से 5 चम्मच नमक

विधि

एक-एक नींबू को 4 टुकड़ों में काटकर उसमें नमक डालकर नर्म होने के लिए 25 दिन से 30 दिन के लिए एक जार में रख दें बीच-बीच में नींबू को चलाते और देखते रहें। जब नींबू नर्म हो जाए तो नींबू में शक्कर, काला नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और बड़ी इलाइची का पाउडर मिलाकर 3 से 4 दिन के लिए धूप में रख दें। हर दिन साफ और सूखे चम्मच से अचार को जरूर चलाएं। एक सप्ताह में नींबू का मीठा अचार अच्छे से बन जाएगा। ध्यान रखें अचार को हमेशा साफ और सूखे चम्मच से ही लें।

ब्रेड भटूरे

साम्रगी

मैदा दो कप, सूजी एक स्पून, ब्रेड स्लाइस आठ, नमक स्वादानुसार, दही तीन स्पून, जीरा आधा टी स्पून, तेल अवयस्कता अनुसार

विधि

सबसे पहले आप ब्रेड की स्लाइस के चारों किनारों के ब्राउन कलर के पार्ट को हटा दीजिए और ब्रेड स्लाइस के सफेद भाग को मिक्सी से पीस लीजिए। अब ब्रेड पाउडर को एक बाउल में डाले और उसमे मैदा, जीरा, सूजी, नमक, दही डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। अब उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें और गुंथे हुए आटे को ढक्कर थोड़ी देर साइड पर रख दीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम कीजिए। अब आटे से लोई तोड़ कर छोटी-छोटी लोई बनाईए। अब आटे की लोई लेकर रोटी की तरह भटूरा बेल कर गरम तेल में डालें। धीमी आंच पर भटूरे को दोनों तरफ से तलकर प्लेट में निकाल कर अलग रख लीजिए। उसके बाद हरी धनिया, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और नींबू के स्लाइस से सजाकर परोसें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : प्रदीप शील ● सहयोगी संपादक : रवि शंकर चौधरी ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**